



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (1)  
PART II—Section 3—Sub-section (1)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 463]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 16, 1991/अग्रहायण 25, 1913

No. 463] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 16, 1991/AGRAHAYANA 25, 1913

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या वाली है जोसे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a  
separate compilation

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय  
(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 दिसम्बर, 1991

सा.का.नि. 739(प्र):—केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नवमंगलूर पत्तन न्यासी मंडल द्वारा बनाए गए और इस अधिसूचना के साथ संसद अनुसूची में नवमंगलूर पोर्ट कर्मचारी (सामान्य भविष्य निधि) विभिन्नम, 1991 का अनुमोदन करती है।

7. उक्त विनियम, इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. पी.आर.-12016/10/91 पी.ई. I (खंड II)]  
अशोक जोशी, संयुक्त भविष्य

नव मंगलौर पत्तन न्यास, (सामान्य भविष्य निधि) प्रथम संशोधन विनियम, 1991

महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 (1963 का 38) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नव मंगलौर पत्तन न्यास मंडल, उपर्युक्त अधिनियम की धारा 124 के अधीन, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के अध्ययीन नव मंगलौर पत्तन न्यास कर्मचारी (सामान्य भविष्य निधि) विनियम, 1980 (28 मार्च, 1980 के भारत का राजपत्र अमाधारण में जी.एस.आर. 157 (ई) के रूप में प्रकाशित) में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाते हैं:—

1. (i) इन विनियमों को नव मंगलौर पत्तन न्यास कर्मचारी (सामान्य भविष्य निधि) विनियम प्रथम संशोधन विनियम, 1991 कहा जाएगा।
- (ii) ये विनियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि को प्रवृत्त होंगे।

2. नव मंगलौर पत्रन न्यास (सामान्य भविष्य निधि) विनियम, 1980 ) जो इसमें इसके बाद उपर्युक्त विनियम के रूप में उल्लिखित है) के विनियम 1 की अधारा (ज) और साथ ही साथ उपविनियम (इ) की उप धारा के अंत में निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा ।

“छोटे भाई, अविवाहित बहनें एवं माता-पिता और यदि अभिदाता के माता-पिता जीवित नहीं हैं तो पितामह या पितामही ।”

3. उपर्युक्त विनियम के विनियम 5 के उपविनियम 4 को निकाल दिया जाएगा और उप विनियम 5 तथा 6 को क्रमशः 4 और 5 के रूप में पुनः संखांकित किया जाएगा । निम्नलिखित को उप विनियम 6 के रूप में रखा जाएगा ।

“इस नियम के प्रयोजन के लिए शिशुओं और परिवेशाधीनों को अस्थायी सरकारी कर्मचारी की तरह माना जाएगा ।”

4. उपर्युक्त विनियमों के विनियम संख्या 6 में उप विनियम संख्या 1 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रथम परंतुक विवरण उपबंध से पूर्व रखा जाएगा ।

“बशर्ते जबकि अभिदाता अवश्यक है तो ऐसे स्थिति में वह वयस्कता प्राप्त कर लेने पर नामांकन भरेगा” इस उप विनियम के प्रथम और द्वितीय परंतुकों को द्वितीय एवं तृतीय परंतुक पढ़ा जाएगा ।

विनियम के अंतर्गत निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा ।

“टिप्पण :—इस नियम में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, “व्यक्ति” या “व्यक्तियों” के अंतर्गत कपनी या एसोसिएशन या अप्लिट निकाय आएंगे जाहे वे निगमित में हो या न हो । इसमें प्रशान्तमंडी का राष्ट्रीय राहत कोष या कोई भी पूर्व न्यास या अन्य न्यास या निधि भी शामिल होंगे, जिनके लिए नामांकन, सचिव या अन्य कार्यकारी के द्वारा किया जा सकता है जो अदायगी प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत हों ।”

5. उपर्युक्त विनियमों के विनियम संख्या 7 को निम्न रूप में उपांतरित किया जाएगा :

“7 अभिदाता लेखा/प्रत्येक अभिदाता के नाम का एक लेखा खोला जाएगा जिसमें निम्नलिखित सूचना होगी :

(i) उसके अभिदाता की राशि ।

(ii) विषम 12 के अनुसार अभिदाता पर ब्याज की राशि ।

(iii) निधि से लिए गए अप्रिमों तथा आहरणों की राशि ।”

6. अपर्युक्त विनियमों के विनियम संख्या 8 में उप विनियम संख्या (1) में निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा : “टिप्पण : अकार्य दिन के रूप में मानी गई अवधि के दौरान अभिदाता को अभिदाता करने की आशयकता नहीं है ।”

विनियम के अंतर्गत उप विनियम संख्या (3) और (4) के रूप में निम्नलिखित उप विनियम जोड़ा जाएगा :

“(3) अभिदाता ने यदि नियम 21 के अधीन निधि में से अपने खाते में जमा राशि निकाल ली है तो वह इस प्रकार निकाली गई राशि के पश्चात् निधि में अभिदाता जब तक नहीं करेगा जब तक कि वह कार्य पर लीट नहीं आता ।”

“(4) उप नियम (1) के अंतर्गत कोई बान होने हुए भी, अभिदाता निधि में उस माह अभिदाता नहीं करेगा जिस माह वह नौकरी छोड़ना है । यदि वह उक्त मास के लिए अभिदाता करना चाहता है तो उसे उक्त मास के प्रारंभ होने से पूर्व इस संबंध में कार्यात्मक प्रधान को लिखित रूप में सूचित करना होगा ।”

विनियम 8 में निम्नलिखित उप विनियम (5) एवं (6) के रूप में जोड़ा जाएगा ।

(5) “अधिवर्षिता पर सेवा-निवृत्त होने वाले कर्मचारी को अपनी सेवा के अंतिम तीन महीनों के दौरान निधि में अभिदाता करने की छुट्टी होगी । इस प्रकार अभिदाता को बंद करता “वैकल्पिक” न होकर अनिवार्य होगा ।”

(6) “ऐसे अभिदाता जो पी.एल.बी. या निष्पादन पुस्कार के हकदार हैं, यदि वे चाहें तो योजना के अंतर्गत स्वीकार्य राशि के सम्बर्ण या उसके किसी भाग को अपने अविष्य निधि खाते में जमा कर सकते हैं ।”

7. उपर्युक्त विनियमों के विनियम 9 में उप विनियम (2) की उप धारा (क) के अधीन परंतुक (1) को निम्नलिखित रूप में उपांतरित किया जाएगा ।

“(1) यदि अभिदाता उक्त तारीख को छुट्टी पर था और उसने छुट्टी के दौरान निधि में अभिदाता न करने का चयन किया हो या उक्त तारीख को निलंबित हो, तो उसकी परिलिंगियां वह परिलिंगियां होंगी जिसका हकदार वह कार्य पर लोटने के प्रथम दिन पर था ।

8. इन विनियमों के विनियम 12 में उप विनियम 1 के अंतर्गत परंतुक 1 में दूमरी, तीकरी और चौथी पंक्ति में आ रहे ब्याज के प्रतिशत को 4 प्रतिशत के स्थान पर 8 प्रतिशत पढ़ा जाएगा ।

उपर्युक्त विनियमों के विनियम 12 में उप विनियम 4 के अधीन निम्नलिखित दूमरा परंतुक विवरण परंतुक के आगे जोड़ा जाएगा :

“रंतु यह और कि जब कि अभिवाता सरकार के स्वामित्व वा नियंत्रण वाले निगमित निकाय या सोसायटी रजिस्ट्री-करण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन किसी स्वायत्त संगठन में प्रतिनियुक्ति पर होने पर, बाबू में उक्त निगमित निकाय या संगठन में भूतलक्षी तारीख से आमेलित हो जाना है तो अभिवाता के नाम जमा संचित निधि पर ब्याज के परिकलन के प्रयोजन के लिए आमेलित से संबंधित आदेश जारी करने की तारीख को अभिवाता की जमा राशि की अशायगी की तारीख माना जाएगा, यह इस शर्त के साथ कि अमेलित की तिथि तथा आमेलित के आदेश जारी करने की तिथि के बीच के समय तक अभिवाता द्वारा जमा की गई अभिवाता की राशि को, इस उप विनियम के अंतर्गत, केवल निधि में ब्याज के लिए जमा की गई राशि ही माना जाएगा।”

निम्नलिखित उप विनियम के अधीन उप विनियम संख्या 6 और 7 के रूप में जोड़ा जाएगा :—

“(6) विनियम 11, विनियम 21 या विनियम 22 के उप विनियम (3) के अधीन अभिवाता के नाम निधि में प्रतिस्थापित राशियों पर ब्याज का आकलन उप विनियम (1) अधीन उत्तरोत्तर विहित दरों पर और उस रीति के अनुसार किया जाएगा जैसा कि इस विनियम में उल्लिखित है।”

विनियम के अधीन निम्नलिखित उप विनियम संख्या 4 के रूप में जोड़ा जाएगा :—

“(1) जब किसी पिछले अग्रिम की अंतिम किश्त के चुकाने से पूर्व उप विनियम (2) के अधीन कोई अग्रिम मंजूर किया जाता है तो इस प्रकार मंजूर अग्रिम राशि में पिछले अग्रिम की न वसूली गई राशि को जोड़ दिया जाएगा और वसूली जाने वाली राशि की किश्तों का निर्धारण समेकित राशि के आधार पर किया जाएगा।”

उपर्युक्त विनियमों के विनियम 14 में निम्नलिखित को उप विनियम (5) के रूप में जोड़े :—

(5) “सेवा के अंतिम तीन माह के दौरान काह भी अस्थायी अग्रिम मंजूर नहीं किया जाएगा ताकि लेखा अधिकारी सेवा निवृत्ति के एक माह पूर्व भुगतान आदेश जारी करने का कार्य पूरा कर सकें।” फार्म नं. VI “भविष्य निधि से अग्रिम के लिए आवेदन-पत्र के प्रोक्टर्स को संलग्न फार्म से प्रतिस्थापित किया जाएगा।”

11. उपर्युक्त विनियमों के अधीन विनियम संख्या 15 में, उपर्युक्त विनियम संख्या (3) के अधीन निम्नलिखित परंतुक को रखा जाएगा :—

“बशर्ते इस प्रकार का अग्रिम नामंजूर करने के पूर्व अभिवाता को, अग्रिम की बापसी क्यों न लागू की जाए ऐसी सूचना मिलने की तारीख से 15 दिन के भीतर मंजूरीदाता प्राधिकारी लिखित रूप में अपना स्पष्टीकरण देने का अवसर दिया जाएगा और यदि अभिवाता उक्त पंद्रह दिन की अवधि के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर देता है तो उस निर्णय के

लिए अध्यक्ष को भेजा जाएगा और यदि उक्त अवधि के भीतर अभिवाता द्वारा कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो इस उप विनियम में विहित रीति से वसूली को लागू कर दिया जाएगा।”

12. उपर्युक्त विनियमों के विनियम संख्या 16 को निम्नलिखित रूप में उपांतरित किया जाएगा :—

“16 अग्रिम का सदोष उपयोग—इस विनियम में किसी प्रावधान के होने हुए भी, यदि मंजूरीदाता प्राधिकारी के पास इस प्रकार का संदेह करने की उचित कारण है कि विनियम 14 के अधीन निधि से निकाली गई अग्रिम राशि का उपयोग मंजूर किए गए प्रयोजन के अलावा अन्य प्रयोजन पर किया गया है, तो वह अभिवाता को अपने संदेह के कारण सूक्ष्म करेगा और अभिवाता को उक्त सूचना मिलने की तारीख से 15 दिन के भीतर लिखित रूप में रह उत्तर देना होगा कि क्या उसने अग्रिम राशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया है जिसके लिए उस वह अग्रिम मंजूर किया गया था। यदि उक्त 15 दिन की अवधि में अभिवाता द्वारा प्रस्तुत किए गए स्पष्टीकरण से मंजूरीदाता प्राधिकारी संतुष्ट नहीं है तो मंजूरीदाता प्राधिकारी को प्रश्नगत राशि को तत्काल निधि में जमा करने के लिए आदेश दे सकता है या ऐसा न करने पर, अभिवाता की परिलिखियों में से एकमुक्त रूप में कठीनी करने के आदेश दे सकता है जोहे अभिवाता छहटी पर भी हो। फिर भी, यदि संदाय की पूर्ण राशि अभिवाता की परिलिखियों के आधे से अधिक हो तो उसकी परिलिखियों की आधी राशि के रूप में मासिक किश्तों के हिसाब से वसूली जाने वाली राशि तब तक काटी जानी चाहिए जब तक की पूरी राशि पूरी न हो जाए।”

टिप्पण :—विनियम में “परिलिखियों” पद में निर्वाह-अनुदान सम्मिलित नहीं है।

13. उपर्युक्त विनियमों के अधीन विनियम 17 में उप विनियम संख्या (2) की प्रथम चार पक्षियों निम्नलिखित रूप में उपांतरित की जाएँगी :—

“(2) अभिवाता द्वारा (10 वर्ष) की सेवा (सेवा की खंडित अवधियों सहित, यदि कोई हो) पूरी करने के पश्चात् या अधिवर्धिता पर सेवा निवृत्ति की तारीख के पूर्व दस वर्ष के भीतर, जो भी अवधि पहले हो, निधि में उसके खाले में जमा राशि में से निम्न किसी एक या अधिक प्रयोजनों के लिए रकम निकाली जा सकती है, यथा ;

विनियम के अधीन उप विनियम (2) के अंतर्गत निम्नलिखित को उप विनियम (ग) के रूप में जोड़ा जाएगा और विद्यमान उपर्युक्त विनियम को उप विनियम (घ) के रूप में पुनः अंकित किया जाएगा :—

(ग) कार्य के स्थान से अलग स्थान पर पैतृक गृह के नवीकरण, परिवर्तन या परिवर्धन या रखरखाव के लिए या नव मंगलीर पत्तन न्यास से प्राप्त कर्ज की सहायता से कार्य स्थान से अलग स्थान पर बनाए गए गृह के लिए”

विनियम के अधीन निम्नलिखित की उप विनियम (3) तथा (4) के रूप में जोड़ें :—

“(3) अभिदाता की सेवा-निवृत्ति की तारीख से पहले छह माह के भीतर निधि में उसके नाम जमा राशि में से फार्म भूमि या कारबाहर परिसर या दोनों के अर्जन के लिए।”

“(4) वित्तीय वर्ष की अवधि में केवल एक बार, अभिदाता द्वारा स्ववित्त और अंशदायी आधार पर नव मंगलौर पत्तन न्यास के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा कर्मचारियों के लिए आयोजित समूह बीमा योजना के अन्तर्गत प्रदा किए गए एक वर्ष के अभिदाता की राशि के समकक्ष।”

विनियम के अधीन टिप्पण 2 को टिप्पण 6 के रूप में पढ़ा जाएगा और निम्नलिखित को टिप्पण 1 से 5 के रूप में रखा जाएगा :—

“टिप्पण 1. यदि अभिदाता ने, गृह निर्माण के लिए नव मंगलौर पत्तन न्यास से अप्रिय प्राप्त किया है या उसे इस संबंध में किसी अन्य मान्यता प्राप्त आवास योजना के अन्तर्गत कोई सहायता प्राप्त करने की अनुमति मिली है तो यह इस विनियम के उप विनियम 2 की उप धारा (क), (ग), (घ) के अधीन विनिर्विष्ट प्रयोजनों के लिए रकम निकालने के लिए और साथ ही नियम 18 के उप विनियम 1 के परन्तुक में विनिर्विष्ट सीमा के भीतर उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत लिए गए किसी कर्ज की वापसी के लिए भी हकदार होगा।

यदि अभिदाता के पास पैसुक गृह है या उसने कार्य के स्थान से अलग स्थान पर सरकार से कर्ज लेकर गृह निर्माण किया है तो वह अपने कार्य स्थान पर गृह स्थल की खरीद के लिए या एक और गृह के निर्माण के लिए या तैयार फ्लैट के अर्जन के लिए इस विनियम के अन्तर्गत अंतिम आहरण के लिए हकदार होगा।

टिप्पण 2—इस विनियम के उप विनियम 2 की उप धारा (क), (ग) और (घ) के अधीन आहरण तभी मंजूर होगा जबकि अभिदाता निर्माण किए जा रहे गृह या किए जाने वाले परिवर्तन या परिवर्धन से संबंधित योजना को, जहां पर स्थल या गृह स्थित हो उस क्षेत्र के स्थानीय नगर-पालिका निकाय से सम्बन्धित रूप से अनुमोदित कराके प्रस्तुत करेगा और यह केवल उन्हीं मामलों में दिया जाएगा जबकि वास्तविक रूप से योजना अनुमोदित हो जाएगी।

टिप्पण 3 :—उप विनियम 2 की उप धारा (ख) के अन्तर्गत आहरण की राशि आवेदन की तारीख पर शेष जमा राशि के तीन चौथाई से अधिक नहीं होनी जिसमें से उपधारा (क) के अधीन पिछले आहरण की राशि को घटा दिया जाएगा। फार्मला इस प्रकार होगा : तीन चौथाई (आवेदन की तारीख पर शेष राशि तथा प्रशंगत गृह के लिए पिछले आहरणों को जोड़कर) में से पिछले आहरण की राशि को घटाकर।

टिप्पण 4 :—उप विनियम 2 की उप धारा (क) के अधीन आहरण उस स्थिति में भी मंजूर किया जाएगा जबकि गृह स्थल या घर परन्ती या पति के नाम में ही बदले पत्ती या पति अभिदाता द्वारा किए गए नामांकन में भविष्य निधि प्राप्त करने वाला प्रथम नामित व्यक्ति हो।

टिप्पण 5 :—इस नियम के अधीन एक ही प्रयोजन के लिए एक बार आहरण अनुमत होगा। परन्तु अलग अलग बच्चों का विवाह या शिक्षा या विभिन्न प्रवसरों पर बीमारी या उस गृह या फ्लैट में परिवर्तन या परिवर्धन जिसका नवीन प्लान, जहां वह गृह या फ्लैट स्थित है, स्थानीय नगरपालिका निकाय द्वारा सम्बन्धित रूप से अनुमोदित है, उनको एक ही प्रयोजन नहीं माना जाएगा। उप विनियम (2) की उपधारा (क) या उपधारा (ग) के अन्तर्गत वित्तीय या तत्परतात आहरण टिप्पण 3 में निर्धारित सीमा के भीतर ही दिया जाएगा।

निम्नलिखित को उप विनियम 2 के अधीन टिप्पण 7 के रूप में रखा जाएगा :—

टिप्पण 7 :—सेवा के अंतिम तीन माह के दौरान कोई भी आंशिक अंतिम आहरण नहीं दिया जाना चाहिए। फिर भी, असाधारण मामलों के विभागाध्यक्ष की मंजूरी से यह दिया जा सकता है। ऐसे मामले में कर्मचारी को यह भी सूचित कर दिया जाना चाहिए कि सेवा निवृत्ति से एक माह पूर्व अंतिम अदायगी के आदेश जारी करने में विलंब की संभावना हो सकती है। निम्नलिखित को उप विनियम संख्या 5 के रूप में जोड़ा जाएगा।

“(5) निम्नलिखित मामलों में भी सामान्य भविष्य निधि से आंशिक अंतिम अंतिम आहरण अनुमत होगे।

(क) उन कर्मचारियों ने जिन्होंने 15 वर्ष की सेवा (सेवा की खंडित अवधि को मिलाकर यदि कोई हो) पूरी कर ली है या जिनके अधिविधित की शायु प्राप्त करने में पांच वर्ष से कम रह गए हैं उन्हें मोटर कार/मोटर साइकिल या स्कूटर आदि खरीदने या इस प्रयोजन के लिए पत्तन से लिए कर्ज की वापसी के लिए उनके भविष्य निधि खाते से आंशिक अंतिम आहरण निम्न शर्तों के अधीन दिया जा सकता है :

(1) मोटर साइकिल/स्कूटर के मामले में कर्मचारी का मूल बेतन 3500 रुपए के समतुल्य होना चाहिए।

(2) मोटर कार खरीदने के लिए आहरण राशि की सीमा 25,000 रुपये तथा मोटर साइकिल/स्कूटर आदि खरीदने के लिए आहरण राशि की सीमा 4000 रुपए होगी। यदि इन बाह्यों को खरीदने के लिए बुकिंग कराने के लिए जमा राशि का आहरण पहले किया गया है तो कर्मचारियों को शेष राशि का आहरण करने की अनुमति विनियमों में विहित कुल सीमा के अनुसार ही होगी। इस प्रयोजन (बुकिंग के लिए जमा राशि और खरीद करने के लिए अपेक्षित राशि को जोड़कर) के लिए आहरण की कुल राशि, आहरण की तिथि

पर अभिवाता के भविष्य निधि खाते में जमा राणि (व्याज सहित) का 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए या बाहन का वास्तविक मूल्य जो भी कम हो, होगी।

(iii) 36 किलों में लौटाए जाने वाले अग्रिम को अध्यक्ष विशेष मामलों में उन कर्मचारियों को अनुमत कर सकता है जिनका 15 वर्ष की न्यूनतम सेवा अवधि पूरी होने में छह मास का समय शेष है।

(iv) उपर्युक्त (iii) के अनुसार अग्रिम प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को 15 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने के पश्चात अग्रिम राणि के बकाया शेष को अंतिम आहरण में बदलने की छूट दी जा सकती है।

(v) इस प्रकार के आहरण एक बार ही अनुमत हों।

(ख) जिन कर्मचारियों ने 28 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है या जिनके अधिविधिता की आयु प्राप्त करने में तीन वर्ष से कम रह गए हैं, उन्हें निम्नलिखित गतों के अधीन अपनी मोटर कारों की व्यापक मरम्मत या ओवरहॉल के लिए भविष्य निधि खाते से अंतिम आहरण लेने की अनुमति दी जा सकती है:—

(i) वे कर्मचारी जिनका वेतन 1400 रुपए के समतुल्य है।

(ii) आहरण की सीमा राणि निम्नलिखित में से जो भी कम हो, वह होगी, यथा; 5000 रुपए या अभिवाता के भविष्य निधि खाते में जमा राणि की एक तिक्काई राणि या मरम्मत या ओवरहॉल की वास्तविक राणि

(iii) कार की खरीद के साथ से कम से कम पांच वर्ष बीत जाने के पश्चात यह आहरण अनुमत होगा। बरती हुई कार के मामले में प्रथम क्रेता द्वारा खरीद की प्रारंभिक निधि को ध्यान में रखा जाएगा।

(iv) इस प्रकार का आहर अभिवाता के पूरे सेवा काल में केवल एक बार ही अनुमत होगा।

(ग) जिन कर्मचारियों ने 15 वर्ष की सेवा अवधि (खंडित सेवा अवधि को मिलाकर यदि कोई हो) पूरी कर ली है उन्हें, निम्नलिखित गतों के अधीन मोटरकार/मोटर साइकिल/स्कूटर/मोपेड आदि की बुकिंग के लिये सामान्य निधि खाते से आंशिक अंतिम आहरण करने के लिए अनुमत किया जा सकता है:

(i) कर्मचारी केंद्रीय सरकार के वेतनमानों में भूल वेतन मोटर कार के लिए 3500 रु. के सम-

सुल्य और मोटर साइकिल/स्कूटर आदि के लिए 1500/- रु. होना चाहिए।

(ii) आहरण राणि की सीमा, निम्नलिखित में से जो भी कम हो वह होगी, यथा; मोटरकार के लिए 10000 रु. तथा मोटर साइकिल/स्कूटर आदि के लिए 500 रुपए या अभिवाता के भविष्य निधि खाते में जमा राणि का 50 प्रतिशत या मोटर साइकिल/स्कूटर आदि के मामले में रजिस्ट्रेशन की वास्तविक राणि।

(iii) आहरण की राणि, कार या मोटर साइकिल या स्कूटर आदि की बुकिंग की अपेक्षित राणि से किसी भी स्थिति में अधिक नहीं होगी।

(iv) जमा रसायांश, संवधित प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा सत्यापन के लिए आहरण लेने की तारीख में एक माह के भीतर अवश्य प्रस्तुत की जानी चाहिए। ऐसा न करने पर आहरण की पूरी राणि वापिस करनी पड़ेगी।

(v) यदि कर्मचारी कार/मोटर साइकिल/स्कूटर आदि नहीं खरीदता है या योजना से अलग हो जाता है तो उसे तत्काल अंतिम आहरण की राणि, विनिर्माता/डीलर से उस पर प्राप्त ध्याज सहित भविष्य निधि खाते में जमा कर देनी चाहिए।

(vi) ऐसे विशेष मामलों में, जहां 15 वर्ष की न्यूनतम सेवा की अवधि छह माह से कम होती है तो 36 किलों में वसूला जाने वाला अग्रिम मंजूर किया जा सकता है और यह अग्रिम 15 वर्ष की सेवा पूरी होने पर आंशिक आहरण में परिवर्तित किया जा सकता है।

(vii) इस प्रकार का आहरण केवल एक अवसर पर सामान्य भविष्य निधि में आहरण के लिए विहित वर्तमान सीमा के अधीन ही अनुमत किया जा सकता है।

निम्नलिखित उप विनियम संख्या 6 के रूप में जोड़ा जाएगा:—

(6) यदि अभिवाता नवीनतम उपलब्ध विवरण के साथ के अभिवातन की जमा राणि के साथ सहित अपने सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा राणि के बारे में सक्षम प्राधिकारी को संतुष्ट कर देता है तो सक्षम प्राधिकारी वापिस किए जाने वाले अग्रिम की भाँति ही स्वयं विहित सीमाओं के भीतर आहरण की मंजूरी दे सकता है। ऐसा करते समय, सक्षम प्राधिकारी अभिवाता को पहले से मंजूर किए गए किसी आहरण या वापिस किए जाने वाले अग्रिम को ध्यान में रखेगा। जब कभी अभिवाता अपनी जमा राणि के संबंध में सक्षम प्राधिकारी को संतुष्ट नहीं कर पाता है या मार्गी गई आहरण की राणि की स्वीकार्यता के संबंध में कोई संदेह हो तो सक्षम प्राधिकारी

को अभिदाता के नाम जमा राशि के संबंध में लेखा अधिकारी से सूचना मांगनी चाहिए ताकि सक्षम प्राधिकारी आहरण की राशि की स्वीकार्यता का निर्धारण कर सके। आहरण की मंजूरी में प्रमाण रूप से सामान्य भविष्य निधि लेखा संख्या दी जानी चाहिए और मंजूरी की एक प्रति सदैव ही लेखा अधिकारी को पूछांकित का जानी के चाहिए। यदि मंजूर किए गए आहरण की राशि अभिदाता नाम जमा राशि से अधिक है या अन्यथा अस्वीकार्य है तो अभिदाता को आहरित राशि को एक मुश्त रूप में निधि में वापिस जमा करना होगा और ऐसा न करने पर सक्षम प्राधिकारी अभिदाता की उपलब्धियों में से एकमुश्त रूप में या उन भासिक किस्तों में वसूल करने के आदेश देगा जैसा कि अध्यक्ष निर्धारित करेगा।

14. उपर्युक्त विनियमों के विनियम 18 के अधीन उप विनियम (1) में निम्नलिखित परन्तुक एवं टिप्पण रखें जायेंगे :—

“बास्ते किसी भी स्थिति में विनियम 17 के अधीन उप विनियम 2 में विनिर्दिष्ट प्रयोजनां के लिए आहरण की अधिकतम राशि, गृह निर्माण के लिए अग्रिम प्रदान करने हेतु नव मंगलोर पत्तन न्यास कर्मचारी (गृह-निर्माण के लिए अग्रिम प्रदान करना) विनियम 1980 के अधीन विनियम 4, 5 और 6 में समय समय पर विहित अधिकतम सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए।

“बास्ते उस अभिदाता के मामले में जिसने नव मंगलोर पत्तन न्यास कर्मचारी (गृह निर्माण के लिए अग्रिम प्रदान करना) विनियम 1980 के अधीन पहले हो अग्रिम से रखा है या किसी अन्य अनुमोदित योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त कर चुका है तो इस उप विनियम के अंतर्गत निकाली गई राशि और उपर्युक्त स्रोतों गे ली गई राशि नव मंगलोर पत्तन न्यास कर्मचारी (गृह निर्माण के लिए अग्रिम प्रदान करना) विनियम, 1980 के अधीन समय-समय पर विहित अधिकतम सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए।

टिप्पण :—विनियम 17 के उप विनियम 1 की उगाहारण (1) के अधीन अभिदाता को मंजूर की गई आहरण की राशि मंजूरी की तारीख से 12 महीनों की प्रवधि में यह अधिक से अधिक चार किस्तों में निकाला जा सकती है।

टिप्पण 2 : उस मामले में जबकि अभिदाता को खरीदे गए स्थान, गृह या फ्लैट के लिए या भारत सरकार द्वारा अनुमोदित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत या भवन निर्माण सहकारी समिति द्वारा निर्मित गृह या फ्लैट के लिए किस्तों में भुगतान करना पड़ता है, तो उसे जब भी किसी भी किस्तों में भुगतान करने के लिए कहा जाता है उसे आहरण करने की अनुमति दी जाएगी। ऐसे प्रत्येक भुगतान को विनियम 17 के उप विनियम (2

के प्रयोजन, के लिए अलग प्रयोजन के लिए भुगतान समझा जाएगा।”

विनियम के अंतर्गत उप विनियम 2 के अधीन निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा :—

“बास्ते इस उप विनियम के अधीन आहरण की राशि वी वापसी की कार्रवाई करने से पूर्व अभिदाता को कार्रवाई वापसी की कार्रवाई क्यों न की जाए ऐसे सूचना मिलने की तारीख से 15 दिन के भीतर अपना निखित स्पष्टीकरण देने का अवसर दिया जाएगा और यदि मंजूरीदाता प्राधिकारी दिए गए स्पष्टीकरण में संतुष्ट नहीं होता है या उक्त 15 दिन की अवधि के भीतर अभिदाता द्वारा कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो मंजूरीदाता प्राधिकारी इस उप विनियम में विहित गीते के अनुसार वापसी की कार्रवाई को लागू कर सकता है।”

विनियम के अंतर्गत उप विनियम (3) के अधीन निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा :—

“बास्ते इस प्रकार की अनुमति तब आवश्यक नहीं होगी जबकि इसे आवासीय बोर्ड, राष्ट्रीयकृत बैंक, जीवन बीमा निगम केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व अथवा नियन्त्रण के अधीन किसी अन्य निगम के पास बंधक रखा जाता है जो नए गृह के निर्माण के लिए या विद्यमान गृह में परिवर्तन या परिवर्धन करने के लिए कर्ज देते हैं।

उप विनियम (4) की चाँथी पंक्ति में आ रहे शब्द “ऐसी वापसी” और “और यह आदेश दिया जाएगा” के बीच में, “इस मामले में अभिदाता को अपना पक्ष प्रस्तुत करने की पर्याप्त अवसर देने के पश्चात” शब्दों को रखा जाएगा।

उपर्युक्त विनियम 18 के अधीन निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा :—

टिप्पण : यदि अभिदाता ने नव मंगलोर पत्तन न्यास से कर्ज लिया है और उस बदले में गृह या गृह स्थल को पत्तन न्यास बोर्ड के पास बंधक रखा है तो उसे निम्न रूप में घोषणा पत्र देना पड़ेगा, यथा :—

एतद्वारा मैं प्रमाणित करता हूँ कि सामान्य भविष्य निधि से जिस गृह या गृह-स्थल के निर्माण या अर्जन के लिए मैंने अंतिम आहरण राशि प्राप्त की है वह मेरे कब्जे में है लेकिन पत्तन न्यास बोर्ड के पास बंधक रखा हुआ है।”

विनियम के अंतर्गत निम्नलिखित को उप विनियम 5 के रूप में जोड़ा जाएगा :—

“(5) अभिदाता को किसी भी स्थान पर गृह निर्माण के लिए दूसरा आहरण प्रदान नहीं किया जाना चाहिए यदि उसे उसी स्थान या अन्य स्थान पर इसी प्रयोजन के लिए अंतिम आहरण प्रदान

किया जा चुका है। अन्य शब्दों में अंतिम आहरण एक गृह से अधिक के लिए अनुमत नहीं किया जाना चाहिए।”

15. उपर्युक्त विनियमों में विनियम 19 के अधीन निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा :—

“टिप्पण :—नियम 17 के उप विनियम 1 के प्रयोजन के लिए संपर्कित रूप के समय अभिदाता के नाम जमा लेखे में ब्याज सहित अभिदान की राशि में अग्रिम की बकाया राशि को मिलाकर शेष राशि माना जाएगा। प्रत्येक आहरण को अवलग-अवलग माना जाएगा और यही सिद्धांत एक में अधिक संपर्कित रूप पर लागू होगा।”

उपर्युक्त विनियमों के विनियम 9 में आ रहे “उप विनियम (1) की उप धारा (ब) और (ग)” शब्दों का “उप विनियम (1) में (4)” द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

नीचे रखे फार्म को “फार्म IX(क) अग्रिम को अंतिम आहरण में परिवर्तित करने के लिए आवेदन पत्र” के रूप में अपनाया जाएगा।

### फार्म IX-क (विनियम संख्या 19)

अग्रिम को अंतिम आहरण में परिवर्तित करने के लिए

#### आवेदन-पत्र का फार्म

1. अभिदाता का नाम
2. पद तथा कार्यालय का नाम
3. वेतन
4. भविष्य निधि का नाम एवं नेत्रा संख्या
5. आवेदन करने की तारीख पर इतिशेष (सामान्य भविष्य निधि अभिदाता के मामले में वास्तविक रूप से अभिदान की गई राशि सहित उस पर देय ब्याज सहित
6. (क) अग्रिम की बकाया राशि : जिसे अंतिम आहरण में परिवर्तित करना है
  - (ख) प्राप्त अग्रिम पर देय ब्याज की राशि
7. (क) अग्रिम लेने का प्रयोजन
  - (ख) अग्रिम की श्रद्धायगी की तारीख
  - (ग) मंजूर अग्रिम की राशि
8. मंजूर किए गए अग्रिम के संसूचना का विवरण
9. यदि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए पहले अग्रिम या अंतिम आहरण लिया गया है तो उसका विवरण दें

16. उपर्युक्त विनियमों के विनियम 27 को निकाल दिया जाएगा और विनियम 28, 29, 30 और 31 का पुर्वकाल क्रमशः 27, 28, 29, और 30 किया जाएगा।

17. उपर्युक्त विनियमों के विनियम 30 उप विनियम (क) उप धारा (ii) में दी गई 2300 रुपए की राशि का 2500 रुपए की राशि से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

विनियम के अधीन टिप्पण 5 रखा जाएगा :

“टिप्पण 5 : इस योजना के संबंध में व्यय के बजट प्राक्कलन लेखा अधिकारी द्वारा व्यय की प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर उसी रीति से तैयार किए जायेंगे। जिस प्रकार अस्य सेवा-निवृत्त लाभों के लिए तैयार किए जाते हैं।

प्रमुख विनियम :—

जहाजरानी तथा परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) दिनांक 28 मार्च 1980 जी.एम.आर. 157(इ) में अधिसूचित ।

बी. महापाल, अध्यक्ष

प्रणासनिक अधिकारी,  
नव मंगलोर पत्तन न्याय पानाम्बुर  
मंगलोर-575010

10. (क) आवेदन पत्र की तारीख पर सेवा काल, खंडित सेवा काल को भिन्नाकर, यदि कोई हो  
 (ख) आवेदन पत्र देने की तारीख : पर अधिवर्षिता आयु के लिए सेवा की अवधि  
 (ग) अधिवर्षिका की तारीख :

स्थान :

तारीख :

संख्या

आवेदक के हस्ताक्षर  
तारीख :

उपयुक्त विवरणों की जांच की गई और उन्हें ठीक पाया गया।

सिफारिश करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर  
एवं पदनाम

आवेदन

तारीख :

नव मंगलीर पतन न्यास कर्मचारी (सामान्य भविष्य निधि) विनियम 1980 के नियम 19 के अन्तर्गत कार्यालय के श्री/श्रीमती/कुमारी (प्रयोजन) के लिए 19 को मंजूर तथा बिल संख्या द्वारा आहरित के सामान्य भविष्य निधि अग्रिम की शेष राशि रूपये (रुपये ) का अंतिम आहरण में सामान्य भविष्य निधि लेखा संख्या परिवर्तित करने के लिए एतद्वारा की मंजूरी प्रदान की जाती है।

हस्ताक्षर . . . . .

पद . . . . .

तारीख . . . . .

संख्या . . . . .

प्रति प्रेषित :—

(1) . . . . .  
 (2) . . . . .  
 (3) . . . . . आदि, आदि

हस्ताक्षर . . . . .  
पद . . . . .

## फार्म VI (विनियम 14)

भविष्य निधियों से अग्रिम लेने के लिए आवेदन पत्र का प्रोफार्मा

नव मंगलीर पतन न्यास

विभाग . . . . . /कार्यालय

. . . . . मे अग्रिम के लिए आवेदन पत्र  
(निधि का नाम यहां लिखें)

1. अभिदाता का नाम

2. लेखा संख्या (विभागीय संकेताक्षर सहित)

3. पद

4. बेतन

: रुपये

5. आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख को अभिदाता की जमा राशि निम्नलिखित है :

- (1) वर्ष के विवरण के अनुसार अभिदाता इनिशेप 199... रुपये
- (2) मासिक अभिदाता के रूप में जमा ..... मे ..... रुपये
- (3) रकम वापसी ..... रुपये
- (4) आहरित राशि ..... से ..... तक रुपये
- (5) निवल जमा शेष : रुपये

6. अग्रिम/बकाया राशि तथा अग्रिम लेने का प्रयोजन :

ली गई अग्रिम राशि वर्तमान बकाया राशि  
रुपये ..... रुपये .....

7. अग्रिम की अपेक्षित राशि : रुपये

8. (क) अग्रिम लेने का उद्देश्य :

(ख) आवेदन पर लागू होने वाला नियम :  
(ग) यदि अग्रिम गृह निर्माण के लिए लिया जा रहा है तो निम्न-  
लिखित सूचना दे :—

- (1) भू-खंड का स्थान और माप
- (2) भू-खंड पूर्ण स्वामित्व में है, या पट्टे पर है
- (3) निर्माण की स्परेंड्रा :
- (4) यदि फ्लेट या भूखण्ड आवास : निर्माण सोसायटी से  
खरीदा जा रहा है तो सोसायटी का नाम, स्थान और  
माप आदि का उल्लेख करें
- (5) निर्माण की लागत
- (6) यदि फ्लेट डी.डी. ए. या अन्य आवासी बोर्ड आदि से खरीदा  
जा रहा है तो स्थान, लम्बाई, चौड़ाई आदि का उल्लेख करें
- (ध) यदि अग्रिम बच्चों की शिक्षा के लिए लिया जा रहा है  
तो निम्न ब्यौरा प्रस्तुत करें :

- (1) पुत्र/पुत्री का नाम
- (2) कक्षा तथा संस्था/कालिज जहां अध्ययन कर रहे हैं
- (3) दिवा छात्र है या होस्टल में रहते हैं
- (इ) यदि अग्रिम परिवार के बीमार सदस्य के उपचार के  
लिए अपेक्षित है तो निम्न सूचना प्रस्तुत करें :
- (१) रोगी का नाम और उससे संबंध
- (2) अस्पताल/डिस्पेंसरी/चिकित्सक जहां रोगी का इलाज हो रहा है
- (3) बहिरंग/अंतरंग रोगी
- (5) प्रतिपूर्ति उपलब्ध है या नहीं

टिप्पणी :—8(ग) से 8(इ) के अधीन यिए जाने वाले अग्रिम के लिए किसी प्रमाणपत्र या दस्तावेजी साक्ष की आवश्यकता नहीं है।

9. समेकित अग्रिम की राशि (मद 6 और 7) तथा किस्तों की संख्या

जिसमें इसे वापिस लौटाया जाना है रुपये ..... किस्तों में

10. अभिदाता की आधिक स्थिति का पूरा ब्यौरा जिससे अग्रिम के  
आवेदन के आधिक्य की पुष्टि हो सके।

मैं प्रमाणित करता हूं कि उपर्युक्त विवरण मेरी सर्वोत्तम समझ और विश्वास में ठीक और पूर्ण है तथा इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

दिनांक :

आवेदक के हस्ताक्षर  
नाम .....  
पदनाम .....  
प्रनुभाग/शाखा .....

नव मंगलोर पत्तन स्थाप कर्मचारी (सामान्य भविष्य निधि) विनियम, 1980 में संशोधन

क्रमांक	विनियम जिसमें संशोधन प्रस्तावित है	नव मंगलोर पत्तन स्थाप कर्मचारी (सामान्य भविष्य निधि) विनियम, 1980 में मानिक प्रावधान	प्रस्तावित संशोधन	अधीक्ष्य
1	2	3	4	5
1.	विनियम 2	2. परिभाषाएँ:		
		(क) परिवार का अर्थ है--		
		1. पुरुष अधिवाता के मामले में उसकी पत्नी या पत्नियाँ और उसके बच्चे और अधिवाता के मृत पुत्र की विधवा या विधवाएँ और बच्चे।	“नाबालिग भाई, अधिवाहित बहने और मां-जीमा सी.मी.एस. बाप और यदि अभिवाता के मां बाप जीवित नहीं हैं तो पितामह या पितामही।”	जीमा सी.मी.एस. (जी.पी.एफ.) 1962 में प्राप्त है।
		2. महिला अधिवाता के मामले में, उसका पति और बच्चे और अधिवाता के मृत पुत्र की विधवा या विधवाएँ और बच्चे।	“नाबालिग भाई, अधिवाहित बहने और मां-बाप और यदि अधिवाता के मां बाप जीवित नहीं हैं तो पितामह या पितामही।”	
2.	विनियम 4	4. पालता की शर्तें-		
		1. एक वर्ष की सतत सेवा के पश्चात समस्त अस्थायी कर्मचारी, अंशदायी भविष्य निधि के पात्रों को छोड़कर पुनर्नियुक्त सभी पंशनभोगी और समस्त स्थायी कर्मचारी निधि में अधिवान करेंगे।	4. पालता की शर्तें-	महात्मा गांधी, 1990 में पानम्बूर में राज्य सभा की अधीक्ष्य-मस्थ विधायक भवित्व की बैठक में किए गए सुझाव जिन्हें भूतल परिवहन (पत्तन विंग) मन्त्रालय ने अपने पत्र संख्या पी आर-12016/10/91-पी ई आई तारीख 25-2-91 द्वारा सूचित किया गया।
		2. वे समस्त अस्थायी कर्मचारी जो एक वर्ष की सतत सेवा किसी माह के शीत्र में पूरी करते हैं तो वे निधि में अभिवान पश्चातवर्ती माह से करेंगे।	2. वे समस्त अस्थायी कर्मचारी जो एक वर्ष की सतत सेवा किसी माह के शीत्र में पूरी करते हैं तो वे निधि में अभिवान पश्चातवर्ती माह से करेंगे।	
		3. नियमित रिक्तियों के स्थान पर भर्ती हुए वे अस्थायी कर्मचारी जिनके एक वर्ष से अधिक सेवा में बने रहने की संभावना है वे एक वर्ष की सेवा पूरी होने से पहले किसी भी समय निधि में अभिवान कर सकते हैं।	3. नियमित रिक्तियों के स्थान पर भर्ती हुए वे अस्थायी कर्मचारी जिनके एक वर्ष से अधिक सेवा में बने रहने की संभावना है, वे एक वर्ष की सेवा पूरी होने से पहले किसी भी समय निधि में अभिवान कर सकते हैं।	
		4. बोर्ड, स्लिवेकानुसार किसी आन्य वर्ग के कर्मचारियों से निधि में अभिवान करने की अपेक्षा कर सकता है।	4. वे कर्मचारी जो किसी भी अंशदायी भविष्य निधि में अभिवान करते हैं उनसे निधि में अभिवान करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।	
		5. वे कर्मचारी जो किसी भी अंशदायी भविष्य निधि में अभिवान करते हैं उनसे निधि में अभिवान करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।	5. निधि में कर्मचारी के प्रवेश की प्रक्रिया निम्नलिखित होगी, यथा;	
			(क) आवेदन फार्म-1 प्रस्तुत करना;	
			(ख) लेखा संख्या का आवेदन। कार्यालय प्रमुख कर्मचारियों से एक वर्ष की सेवा पूरी करने के 3 माह पूर्व आवेदन फार्म-1 में प्राप्त कर लेगा।	
		6. निधि में कर्मचारी के प्रवेश की प्रक्रिया निम्नलिखित होगी यथा;		
		(क) आवेदन फार्म-1 प्रस्तुत करना;		
		(ख) लेखा संख्या का आवेदन। कार्यालय प्रमुख कर्मचारियों से एक वर्ष की सेवा पूरी करने के 3 माह पूर्व आवेदन फार्म-1 में प्राप्त कर लेगा।		

## 43. विनियम 6

## 6. नामांकन

1. अभिदाता निधि में प्रवेश के समय लेखा अधिकारी को एक नामांकन पत्र भेजेगा जिसमें राशि देय होने से पूर्व उसकी मृत्यु हो जाने पर या ऐसी स्थिति में जहां राशि देय हो गई है परन्तु अधिकारी नहीं की गई है। एक व्यक्ति या अधिक व्यक्तियों द्वारा निधि में जमा उसकी राशि प्राप्त करने का अधिकार होगा; परन्तु यदि नामांकन भरने समय अभिशानों का परिवार है तो वह नामांकन केवल अपने परिवार के सदस्य या सदस्यों के नाम ही भरेगा।

## 6. नामांकन

1. अभिदाता निधि में प्रवेश के समय लेखा अधिकारी को एक नामांकन पत्र भेजेगा जिसमें राशि देय होने से पूर्व उसकी मृत्यु हो जाने पर या राशि देय हो गई है परन्तु अधिकारी नहीं की गई है, एक व्यक्ति या अधिक व्यक्तियों को निधि में जमा उसकी राशि प्राप्त करने का अधिकार होगा; “परन्तु यदि अभिदाता नावालिंग है तो वह बालिंग होने पर ही नामांकन पत्र भरेगा।

‘परन्तु यदि नामांकन भरने समय अभिदाता का परिवार है तो वह नामांकन के बल प्रपने परिवार के सदस्य या सदस्यों के नाम ही भरेगा;

‘परन्तु यह और कि अभिशान यदि इस निधि में प्रवेश करने से पूर्व अन्य किसी भविष्य निधि में अभिदान कर रहा था और उसके नाम जमा राशि इस निधि में उसके नाम स्थानांतरित हो गई है तो यह समझा जाएगा कि उसने इस विनियम के अधीन विधिवत नामांकन कर दिया है जब तक कि वह इस विनियम के अनुसार नामांकन नहीं भरता है।

टिप्पण :—इस नियम में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो “अक्षित” या “व्यक्तियों में, कौपनी या एसोसिएशन या अटिट्डों का निकाय, जाहे वे निर्गमित हों या न हो शामिल होंगे। इसमें प्रधानमंत्री का राष्ट्रीय राहत कोष या कोई पूर्ण या अन्य न्यास का कोष भी शामिल होंगे जिसके लिए नामांकन सचिव या अन्य कार्यकारी प्राधिकारी के अनिए से किया जाता है, जो राशि प्राप्त करने के लिए सक्षम हो।”

## 4. विनियम 7

## 7. अभिदाताओं के लेखे :

प्रत्येक अभिदाता के नाम में एक लेखा खोला जाएगा जिसमें उसके अभिदान की राशि सहित उस पर विनियम 12 में विहित तरीके से निकाले गए व्याज की राशि के साथ अप्रिमों तथा आहरणों का हिसाब रखा जाएगा।

## 7. अभिदाता का लेखा :

प्रत्येक अभिदाता के नाम एक लेखा खोला जाएगा जिसमें निम्नलिखित को दर्शाया जाएगा :—

- (1) उसके अभिदान की राशि ।
- (2) अभिदान पर नियम 12 में विए छिसाव से व्याज ;
- (3) निधि से लिए प्रत्रिम और आहरण

## 5. विनियम 8

## 8. अभिदान की दरें और शर्तें :

1. अभिदाता अपनी निलंबनाधीन सबधिं को छोड़कर प्रत्येक माह निधि में अभिदान करेगा। परन्तु अभिदाता अपने विकल्प से जाहे तो ऐसी कुट्टी के दौरान जिसमें सूटी बेतन वेय न हो या सूटी बेतन आधे बेतन से कम या समतुल्य हो, अभिदान नहीं करेगा।

1

2

3

4

5

परन्तु यह और कि निलंबनाधीन अवधि के पासान अभिदाता के बहाल हो जाने पर उसे अधिक से अधिक निलंबनाधीन अवधि के लिये वेत्र अभिदाता की बकाया राशि एकमुण्ड या किसी में जमा करने की छूट होगी।

“टिप्पण :—अभिवाता का आकार्य अवधि के दौरान अभिदान देने की आवश्यकता नहीं है।”

(2) अभिदाना (विनियम 8 के उप विनियम (i) के प्रथम परन्तु भी में संदर्भित) छुट्टी के दौरान अभिदान न करने के अपने विकल्प को लिखित रूप में सेवा अधिकारी को देगा। सम्यक रूप से और यथासमय सूचित न करने का अर्थ यह समझा जाएगा कि अभिवाता विनियम के अधीन अभिवाता द्वारा सूचित किया गया विकल्प अंतिम होगा।

“(3) यदि अभिदाता ने निवि में जमा अपनी राशि में से नियम 21 के अधीन आहरण किया है तो इस प्रकार किए गए आहरण के पश्चात् वह तब तक अभिदान नहीं करेगा जब तक कि कार्य पर लौट नहीं आता।”

“(4) उपनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी अभिवाता जिस माह में सेवा से अवलग होता है उस माह के लिए वह जब तक अभिदान नहीं करेगा जब तक कि उक्त माह के प्रारंभ होने से पूर्व वह उक्त माह में अभिदान करने के अपने विकल्प को कार्यालय प्रमुख को लिखित रूप में सूचित नहीं कर देता।”

“(5) अविवरित पर सेवा निवृत्ति होने पर कर्मचारी को सेवा के अंतिम तीन माह में अभिदान न करने की छूट होगी। अभिवाता का बंद किया जाना बैकल्पिक न होकर अनिवार्य होगा।”

“(6) ऐसे अभिवाता जो पी एन बी या निष्पादन पुस्तकार के हकदार हैं, यदि वे वाहें सो योजना के अंतर्गत स्वीकार्य राशि के सम्मुख या उसके किसी भाग को अपने भविष्य निवि ज्ञाते में जमा कर सकते हैं।”

6. विनियम 9

9. अभिदान की दर--

(2)

(क) बारते कि--

1. अभिदाता यदि छुट्टी पर था और उसने छुट्टी के दौरान अभिदान न करने का चयन किया तो उक्त तारीख को उसकी परिलिंग्धियां वह परिलिंग्धियां होंगी जिसका हकदार वह कार्य पर लौटने के प्रथम दिन पर था।

(1) यदि अभिदाता उसन तारीख को छुट्टी पर था और उसने छुट्टी के दौरान निवि में अभिदान न करने का चयन किया हो या उक्त तारीख को निलंबित हो, तो उसकी परिलिंग्धियां वह परिलिंग्धियां होंगी जिसका हकदार वह कार्य पर लौटने के प्रथम दिन पर था।

1 2

3

4

5

7. विनियम 12

12. व्याज—

12. व्याज—

(1.) उप विनियम (5) के उपरांतों के ग्राहकोंने वांछे अभिवाता के जमा खाते में उस दर से व्याज की रकम जमा करेगा जो प्रत्येक वर्ष बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाएगा।  
 परन्तु किसी वर्ष के लिए यदि व्याज की दर 4 प्रतिशत से कम निर्धारित की जाती है तो जिस वर्ष में पहली बार 4 प्रतिशत से कम व्याज की दर निर्धारित की गई है उसके पूर्वकर्ता वर्ष में निधि में अभिवान करने वाले गमी अभिवाताओं को 4 प्रतिशत व्याज दिया जाएगा।

4. विनियम 21, 22 और 23 के अधीन किसी निधि की अदायगी के अनियन्त्रित उस पर विद्या जाने वाला व्याज अदायगी के समय के पूर्वकर्ता माह तक या उस राशि के देव होने वाले माह के पश्चात् 6 माह तक, जो भी अवधि कम हो, उस अवधि को देव होगा जिसे इस राशि का भुगतान किया जाना है।

परन्तु लेखा अधिकारी यदि उस अवधि को (या उसके एजेंट को) नकद भुगतान करने की तारीख सूचित कर देता है तो व्याज सूचित की गई तारीख वे पूर्वकर्ता माह तक की अवधि का या ऐक भेजने की तारीख तक का जैसी भी स्थिर हो, दिया जायगा।

5. यदि अभिवाता लेखा अधिकारी को सूचित करता है कि वह व्याज नहीं लेना चाहता हो व्याज उसके खाते में जमा नहीं किया जाएगा, परन्तु बाद में यदि वह व्याज के लिए कहता है तो उसके व्याज का आकलन, जिस वर्ष में वह कहता है उस वर्ष के प्रथम विन में किया जाएगा और उसके खाते में जमा किया जाएगा।

(1.) उप विनियम (5) के उपरांतों के द्वारा अभिवाता के जमा खाते में उस दर से व्याज की रकम जमा करेगा जो प्रत्येक वर्ष बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाएगी।  
 परन्तु किसी वर्ष के लिए यदि व्याज की दर 8 प्रतिशत से कम निर्धारित की जाती है तो जिस वर्ष में पहली बार 8 प्रतिशत से कम व्याज की दर निर्धारित की गई है उसके पूर्वकर्ता वर्ष में निधि में अभिवान करने वाले सभी अभिवाताओं को 8 प्रतिशत व्याज दिया जायगा।

अन्तुम् 1990 में पानम्बूर में गज्जन सभा की अधीनस्थ विश्वायन समिति की बैठक में यिए गए सुझावों के बादार पर जिन्हें भूतल परिवहन (पत्तन यिंग) मंदालय ने अपने पत्र में श्री आर 12016/10/91 पी ई आई सरीख 25-2-91 द्वारा गूचित किया गया।

“परन्तु यह और कि जबकि अभिवाता सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले नियमित निकाय या सोसायटी रजिस्ट्रीडरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन कर्सी स्वायत्त संगठन में प्रतिनियुक्त पर होने पर, बाद में उक्त नियमित निकाय या संगठन में भूतलक्षी तारीख से आमेलिन हो जाता है तो अभिवाता के नाम जमा संचित निधि पर व्याज के परिकलन के प्रयोगन के लिए आमेलन में संबंधित आवेद जारी करने की तारीख को अभिवाता की जमा राशि की अदायगी की तारीख माना जाएगा; यह इस शर्त के साथ आमेलन की नियंत्रण के आवेद जारी करने की तिथि के बीच के समय तक अभिवाता द्वारा जमा की गई अभिवान की राशि को, इस विनियम के अन्तर्गत, केवल निधि में व्याज के लिए जमा की गई राशि माना जाएगा।”

(6) विनियम 11, विनियम 21 या विनियम 22 के उप विनियम (3) के अधीन अभिवाता के नाम निधि में प्रतिस्थापित राशियों पर व्याज का आकलन उप विनियम (1) के अधीन उत्तरोत्तर विहित दरों पर और उस रीति के अनुसार किया जाएगा जैसा कि इस विनियम में उल्लिखित है।

“(7) यदि ऐसा पाया जाता है कि अभिदाना में निधि में अपनी जमा राशि से प्रधिक राशि निकाली है तो प्रध्यादान की राशि, नाह वह निधि से अग्रिम या आहरण या अंतिम अदायगी के रूप में निकाली गई हो, उसे एकमुक्त रूप में व्याज सहित लोटानी होगी या ऐसा न करने पर उक्त राशि अभिदाना की परिसलविधयों में से एकमुक्त रूप में काट लेने के आवेदन दिए जाते हैं। यदि वसूल की जाने वाली राशि अभिदाना की परिसलविधयों की राशि के माध्ये से अधिक हो, तो उसकी परिसलविधयों की आधी राशि के रूप में मासिक किस्तों के हिसाब से बगूती जाने वाली राशि तथ तक काढी जाती चाहिए जब तक कि व्याज सहित समस्त राशि पूरी न हो जाए।”

8. विनियम 12

9. विनियम 14

13. प्रोत्साहन ओनस स्कीम

14. निधि से अग्रिम (1)

(प) अपने किसी पर्याय अंतिमों के निवृत्त्यमें कार्य करने को तात्पर्यमन्मामले के संबंध में अभिदाना के विरुद्ध लगाए गए आरोपों के बाय निवारण के लिए अभिदान द्वारा संस्थित विधिक कार्यवाहियों के व्यय को वहन करने के लिये अग्रिम राशि दी जा सकती ओ इसी प्रयोजन के लिए अन्य किसी स्कोल से अनुज्ञय किसी अग्रिम के प्रतिरक्त होगी।

(2)

(3)

विनियम 13 को निकाल दिया गया

14(1)

(प) अभिदाना उसके परिवार के सम्बन्ध या वास्तविक रूप से उम पर आकिल किसी व्यक्ति द्वारा या उनके विषद्वंसित विधिक कार्यवाहियों की लागत वो घटन करने के लिए अग्रिम राशि दी जा सकती जो इसी प्रयोजन के लिए अन्य किसी स्कोल (पत्तन) से घनुमेय किसी अग्रिम के प्रतिरक्त होगी।”

(4) यदि किसी पिछले अग्रिम की अंतिम किस्त के चुकाने से पूर्व उप नियम (2) के अधीन कोई अग्रिम मंजूर किया जाता है तो इस प्रकार मंजूर अग्रिम राशि में पिछले अग्रिम की न वसूली गई राशि को जोड़ दिया जाएगा और वसूली जाने वाली राशि की किसी का निर्धारण समेकित राशि के आधार पर किया जाएगा।”

(5) सेवा के अंतिम तीन माह के दौरान कोई भी अस्थायी अग्रिम मंजूर नहीं किया जाएगा ताकि लेखा अधिकारी सेवा निवृत्त के एक माह पूर्व बुगतान आदेश जारी करने का कार्य पूरा कर सके।”

बगते इस प्रकार का अग्रिम नामंजूर करने के पूर्व अभिदाना को अग्रिम की आपसी करों न लागू की जाए ऐसी सूचना मिलने की तारीख से 15 दिन के भीतर मंजूरीदाता प्राधिकारी को लिखित रूप में अपना स्पष्टीकरण देने का आवश्यक किया जाएगा और यदि अभिदाना उक्त 15 दिन की अवधि के भीतर अभिदान द्वारा कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो इस उप नियम में विविध रीति से वसूली को लागू कर दिया जाएगा।

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

10. विनियम 15

15. अप्रिम की वसूली--

(1)

(2)

(3) यदि अभिवाता को अप्रिम मंजूर किया जाता है और वह उसे ये लेना है और वाद में अप्रिम की वापसी पूरा होने से पूर्व नामंजूर कर दिया जाता है तो भास्तव या आहरित राशि की गोल राशि अभिवाता को तत्काल निधि में लौटानी होगी या ऐसा न कर्त्ता पर लेखा अधिकारी विनियम 14 के उपनियम (3) के स्पष्टीकरण 2 के अधीन अध्यक्ष या अप्रिम मंजूर करने वाले मकाम प्राधिकारी के निर्देश पर उसकी पर्याप्तियों में से एकमध्ये रूप में या अधिकतम 12 मासिक किश्तों के रूप में अप्रिम वसूली के आदेश दे राकर्ता है।

## कार्य-VI

विनियम 14 देखें

भवित्व निधि से अप्रिम लेने के लिए आवेदन का प्रोकार्मा

नव भंगवार पत्तन (.....) से अप्रिम लेने के लिए आवेदन पत्र।  
(निधि का नाम)

1. अभिवाता का नाम
2. लेखा संख्या  
(विभाग के नाम सहित)
3. पद :
4. वेतन :
5. आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख को अभिवाता की जमा राशि निम्नलिखित है।
  - (i) ..... के विवरण के अनुसार अभिवाता का इतिशेष
  - (ii) जमा ..... से ..... तक  
अभिवाता की राशि .....
  - (iii) रकम वापसी :
  - (iv) आहरित राशि ..... से ..... तक
  - (v) निवल जमा रेष :
6. अप्रिम की बकाया राशि यदि कोई है और उसे लेने का प्रयोजन
7. अप्रिम की अपेक्षित राशि :
8. (क) अप्रिम लेने का प्रयोजन :
  - (a) आवेदन पर लागू होने वाले नियम :
9. कुल समेकित अप्रिम की राशि : (मध्य 6 और 7 का जोड़) और मासिक किश्तों की संख्या जिसमें इसे वापिस लौटाया जाना है :
10. अभिवाता की आर्थिक स्थिति का पूरा व्यारा जिसमें अप्रिम के आवेदन के औचित्य की पुष्टि हो सके।

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम : .....

पद : .....  
अनुभाग/शाखा : .....

## कार्य-VI

(विनियम 14)

भविष्य निधि से अग्रिम राशि के लिए आवेदन-पत्र का प्रोफार्म

तथा भंगलौर पराम न्याय

विभाग/कार्यालय

..... अग्रिम राशि के लिए आवेदन-पत्र  
(यहाँ निधि का नाम भरें)

1. अभिदाना का नाम

2. खाता संख्या (विभाग का नाम सहित)

3. पद

4. वेतन

रुपय

5. आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख को अभिदाना की जगा निधि निम्नलिखित है:

(i) वर्ष ..... के विवरण के अनुसार इनिषेट

रुपय

(ii) जमा ..... से .....  
मासिक अभिदान की राशि

रुपय

(iii) रकम बापसी

रुपय

(iv) निवाल जमा शेष

रुपय

6. अग्रिम राशि/बकाया राशि, यदि कोई व्या अग्रिम लेने का प्रयोजन प्राप्त  
अग्रिम की राशि रुपय .....  
.....

बर्तमान में बकाया राशि रु. ....

7. अग्रिम की अपेक्षित राशि

रुपय

8. (क) अग्रिम की अपेक्षित राशि

रुपय

(ख) अग्रिम लेने का प्रयोजन

(ग) अवेदन पर लागू होने वाला नियम

(घ) यदि अग्रिम मकान-निर्माण आदि के लिए निया जा रहा है तो निम्न-  
लिखित सूचना दें:—

9. (i) ब्लॉट का स्थान तथा लंबाई-चौड़ाई

(ii) क्या ब्लॉट पूरी स्वामित्व में है या पट्टे पर

(iii) निर्माण का धारा

(iv) फैटेट/ब्लॉट भवन निर्माण सोसायटी से खरीदा जा रहा है तो सोसायटी  
का नाम, स्थान और लंबाई-चौड़ाई इत्यादि

(v) निर्माण की लागत

(vi) यदि फैटेट श्री, जी, प. या अन्य आवासीय बोर्ड आदि से खरीदा जा  
रहा है तो उसके स्थान लंबाई-चौड़ाई आदि वी जानी चाहिए।(घ) यदि अग्रिम बच्चों की शिक्षा के लिए अपेक्षित है तो निम्न सूचना वी  
जानी चाहिए:—

(i) पुत्र/पुत्री का नाम

(ii) कक्षा तथा संस्था/कालिज का नाम जहाँ अध्ययन कर रहे हैं।

(iii) दिवा छात्र हैं या होस्टल में हैं।

(३.) यदि परिवार के वीमार मदस्यों के लिए अप्रिम ग्राहणित हैं, तो निम्न

- (i) सूखना वी जानी चाहिए
- (ii) गोमी का नाम और उसमें संबंध
- (iii) अस्पताल/डिम्बेमरी/चिकित्सक का नाम जट्ठा छापा रहा है
- (iv) क्या बहिरंग/अंतरंग रोगी हैं
- (v) क्या प्रतिपूर्ति उपलब्ध है या नहीं

टिप्पणी:—यदि अप्रिम गाँधि 8(g) से 8(३.) के अधीन चाहिए तो प्रमाण-पत्र या वस्तावेजी माद्य की आवश्यकता नहीं है।

9. कुल अप्रिम (मद 6 और 7 का जोड़)

राशि और किसनों की मंजूरा जिसमें इसे वर्णित नोटाना है।

10. अभिदाता की आर्थिक स्थिति का पूरा व्यौग जिसमें अप्रिम गाँधि के औचित्य की पुष्टि हो सके।

मैं प्रमाणित करता हूँ कि पूर्ण ज्ञान और विश्वास के अनुसार उपर्युक्त विवरण ठीक और पूर्ण है और इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम .....

पद .....

विभाग/ग्राम

दिनांक:—

1 2

3

4

5

11. विनियम 16

16. अप्रिम का सदोष उपयोग:—इन विनियमों की कोई बात होने हुए भी, यदि अस्यक्ष संतुष्ट है कि विनियम (14) के अधीन लिया गया अप्रिम, मंजूर प्रयोजन के लिए उपयोग न करने, किसी अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग किया गया है तो प्रश्नगत राशि अभिदाता को तत्काल निधि में नौटानी होती या ऐसा न करने पर अध्यक्ष अभिदाता की परिलक्षियों में से एकमुश्त वसूली करने के आदेश वे सकाता है चाहे अभिदाता छूट्टी पर ही हो। यदि वसूली जाने वाली राशि अभिदाता की परिलक्षियों की आधी से अधिक हो तो वसूली उसकी परिलक्षियों के अधीन की मासिक किस्तों में तब तक की जाएगी जब तक कि पूरी राशि घमूल नहीं हो जाती।

स्पष्टीकरण:—इस विनियम में “परिलक्षियों में जीवन निर्वाह अनुदान” मन्मतित नहीं है।

“16 अप्रिम का सदोष उपयोग:—इस विनियम में कोई बात होने हुए भी, यदि मंजूरीदाता प्राधिकारी के पास संदेह का कारण है कि नियम 14 के अधीन लिया गया अप्रिम मंजूर प्रयोजन के लिए उपयोग न करके किसी प्रत्ये प्रयोजन के लिए उपयोग किया गया है तो वह अभिदाता को अपने संबंध का कारण सूचित करेगा और उससे प्रपेक्षा करेगा कि वह ऐसी सूखना मिलने के 15 दिन के भीतर लिखित रूप में सूचित करे कि क्या अप्रिम धन उसी प्रयोजन के लिए उपयोग किया गया है जिसके लिए वह मंजूर किया गया था। यदि मंजूरीदाता प्राधिकारी उसके पंद्रह दिन की अवधि के भीतर अभिदाता द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं है तो मंजूरीदाता प्राधिकारी अभिदाता को तत्काल प्रश्नगत राशि को निदि में जमा करने के लिए आदेश देगा या ऐसा न करने पर उसकी परिलक्षियों में से एकमुश्त रूप में कटौती करने के आदेश देगा जाहे वह छूट्टी पर भी हो। यदि वसूली जाने वाली राशि अभिदाता की परिलक्षियों की आधी से अधिक हो तो वसूली, उसकी परिलक्षियों के अधीन की मासिक किस्तों में तब तक की जाएगी जब तक कि पूरी राशि उससे वसूल नहीं हो जाती।”

1

2

3

4

5

12. विनियम 17

17. निधि से आहरण:—

(1)

(2) अभिवाता की 15 वर्ष की सेवा पूरी होने पर या उसकी सेवा नियुक्ति की तारीख से पहले वस वर्ष के भीतर, निधि में उसके नाम अभिदाता की व्याज सहित जमा राशि में से, निम्नलिखित एक या एक से अधिक प्रयोजनों के लिए, यथा:—

(क)

(ख)

(ग) धारा (क) के अधीन आहरित राशि का उपयोग करने के लिए खरीदे गए स्थल पर मकान का निर्माण करने के लिए।

टिप्पण:—नियम में “परिलिखित” पर में जीवन निर्धारित मनुमत सम्मिलित नहीं है।

“(2) अभिवाता की (वस वर्ष) सेवा (खंडित सेवा काल को जोड़कर, यदि कोई हो) पूरी होने पर या प्रधिवर्षिता पर सेवा नियूनि की तारीख से वस वर्ष के भीतर, जो भी पहले हो, निधि में उसके नाम जमा राशि में से निम्नलिखित एक या एक से अधिक प्रयोजनों के लिए, यथा:—

“(ग) कार्य के स्थान से निम्न स्थान पर ऐनुक मकान के नवीकरण, परिवर्तन या परिवर्धन या रख रखाव के लिए या कार्य के स्थान से निम्न स्थान पर नव मंगलौर पतन न्यास से लिए कर्ज की सहायता से बनाए गए मकान के लिए।”

“(ब) धारा (क) के अधीन आहरित राशि का उपयोग करने के लिए खरीदे गए स्थल पर मकान का निर्माण करने के लिए।”

“(3) अभिवाता की सेवा नियुक्ति की तारीख से पहले छह माह के भीतर निधि में उसके नाम जमा राशि में से कार्य भूमि या कारबार परिसर या बोनों को अर्जित करने के प्रयोजन के लिए।”

“(4) विशेष वर्ष में केवल एक बार, अभिदाना द्वारा एक वर्ष में अभिदान के रूप में जमा की गई राशि के बराबर, स्ववित एवं असदान आवार पर नव मंगलौर पतन न्यास के लिए भारतीय जीवन बीमा द्वारा आयोजित कर्मचारियों के लिए समूह बीमा योजना में भवा करने के लिए।”

टिप्पण 1:—विनियम 17 के अधीन एक समान प्रयोजन के लिए केवल एक बार आहरण मनुमत होगा। परम्परा अलग-अलग बच्चों का विवाह/शिशा या विभिन्न द्रव्यसंरोप प्रीमियरी को एक समान प्रयोजन के रूप में नहीं भाला आएगा।

टिप्पण 2:—विनियम 17 के अधीन आहरण मंजूर नहीं किया जाएगा, यदि उसी समय वर, एक समान प्रयोजन

टिप्पण 1:—अभिवाता ने यदि मकान निर्माण के लिए नव मंगलौर पतन न्यास से अप्रिम ले रखा है या किसी अन्य मान्यताप्राप्त आवासीय योजना से कोई सहायता प्राप्त कर रखी है वो वह इस विनियम में विनिविष्ट प्रयोजनों के लिए उप विनियम (2) की उपधारा (क), (ख), (ब) के अधीन और उपर्युक्त योजना के अधीन लिए गए किसी और की अदायगी के

1 2

3

4

5

के लिए विनियम 14 के अधीन अग्रिम मंजूर किया जा रहा है।

प्रयोजन के लिए, नियम 18 के उप नियम (1) के परंतुक में विनियिष्ट मीठा के अनुसार आहरण करने का हकदार होगा।"

यदि अभिदाता ने कार्य के स्थान से भिस्त स्थान पर सरकार से प्राप्त कर्ज की सहायता से मकान बनाया है या उसका वैतुक मकान है, तो वह कार्य के स्थान पर मकान स्थल की खरीद के लिए या अन्य मकान के निर्माण के लिए या बने बनाए फ्लैट का अर्जन करने के लिए, इस विनियम के अधीन अंतिम आहरण करने का हकदार होगा।

टिप्पणी 2:—इस विनियम के उप विनियम (2) की उपधारा (क), (ग) और (घ) के अधीन आहरण नव तक मंजूर नहीं किया जाएगा जब तक अभिदाता जहां स्थल या मकान स्थित है वहां निर्माण किए जाने वाले मकान या परिवर्तन या परिवर्धन करने से संबंधित प्लान को उस क्षेत्र की स्थानीय नगरपालिका निकाय से मम्यक रूप से अनुमोदित कराके प्रस्तुत नहीं करता है। इस प्रकार की भंजूरी उन ही मामलों में वी जापानी जिनमें प्लान वास्तविक रूप से अनुमोदित हो जाता है।

टिप्पण 3:—विनियम 2 की उप धारा (घ) के अधीन, मंजूर की गई आहरण की राशि आवेदन की तारीख पर शेष राशि में उप धारा (क) के अधीन पूर्व आहरण की राशि को मिलाकर दीन जौयाई से अधिक नहीं होनी चाहिए, जिसमें से पिछले आहरण की राशि को निकाल दिया जाएगा। कार्यकारी इस प्रकार है: जीन जौयाई राशि (आवेदन करने की तारीख पर शेष राशि में प्रस्तुत मकान के लिए पिछले आहरणों की राशि को मिलाकर) जिसमें से पिछले आहरण को घटा दिया जाएगा।

टिप्पण 4:—उप विनियम 2 की उप-धारा (क) के अधीन भी आहरण अनुमत होगा यदि मकान स्थल या गृह पती या पति के नाम में हो, बासर्ते अभिदाता द्वाग किए गए नामांकन में वह अधिक्षय निधि राशि प्राप्त करने के लिए प्रथम नामिती है।

1

2

3

4

5

टिप्पण 5:—इस नियम के अधीन एक समान प्रयोजन के लिए केवल एक आहरण अनुमत होगा । परंतु श्रद्धा-श्रमण बन्धों का विदाह या शिक्षा को या विभिन्न अवसरों पर खीमारी को या ऐसे मकान या फैट में और परिवर्तन या परिवर्धन करना जो मकान या फैट के स्थान में संबंधित थोक के रथानीय तार पालिका निकाय में सम्बन्धित रूप से अनुमोदित नए प्लान के अन्तर्गत हो, इन्हें एक समान प्रयोजन नहीं माना जाएगा । उप विनियम 2 की उपधारा (क) या उपधारा (ग) के अधीन दूसरा या बाद का आहरण नियम 3 के अधीन विहित सीमा तक ही सीमित होगा ।”

टिप्पण 6:—विनियम 17 के अधीन आहरण मंजूर नहीं किया जाएगा यदि असी समय पर, एक समान प्रयोजन के लिए विनियम 14 के अधीन प्रथम मंजूर किया जा रहा है ।

टिप्पण 7:—सेवा के अंतिम सीन महीनों में कोई भी आंशिक अंतिम आहरण अनुमत नहीं किया जाना चाहिए । तथापि आपवादिक मामलों में विभागाध्यक्ष की मंजूरी से अनुमत किया जा सकता है । ऐसे मामलों में गंभीरता कमज़ोरी को स्पष्ट रूप में नूचिन कर देता चाहिए कि सेवा नियम से एक माह पूर्व अंतिम आहरण के आदेश जारी करने में विलंब की समस्या है ।

“(5)” निम्नलिखित मामलों गे भी मामान्य भविष्य निधि से प्रांशिक अंतिम/अंतिम आहरण अनुमत है ।

(क) वे कमज़ोरी जिन्होंने 15 वर्ष की सेवा (ब्रॉडलैन सेवा काल, यदि उसे भिसाकर) पूरी कर ली है या प्रिन-को प्रविवर्पिता की आयु पूरी करने में 5 वर्ष से कम रह गए हैं, उन्हें अपने भविष्य निधि योस्त में, मोटर-फार/मोटर साइकिल या स्कूटर प्राविकी अरीद के लिए या इस प्रयोजन के लिए पन्नन में लिए जाएं की बापसी के लिए, आंशिक अंतिम आहरण करने की अनुमति निम्नलिखित पार्टी के अधीन होगी:—

(i) कमज़ोरी का मूल बेतन मोटर कार के मामले में 3500/- रुपए प्रति मास के गमकक्ष और मोटर साइकिल/स्कूटर के मामले में 1500/- रुपए प्रतिमास होना चाहिए ।

(ii) आङ्गण की गणि की रीमा मोटरकार खरीदने के लिए 25000/- रुपए यथा मोटर साइकिल/स्कूटर आदि खरीदने के लिए 4000/- रुपए हैं। ऐसे मामलों जहां इन वाहनों की युकिग करने के लिए आहरण पहले ही किया जा चुका है तो कर्मचारी विहित अधिकारम सीमा गणि के अतीत होगा। इस प्रयोजन (बुकिंग के लिए जमा राशि में खरीद के लिए अपेक्षित गणि को जोड़कर) के लिए आहरित कुल राशि, आङ्गण की जारीब पर, अभिदाना के भविष्य निधि आते में (व्याज सहित) जमा गणि के 50 प्रतिशत भाग से अधिक नहीं या वाहन का वास्तविक मूल्य जो भी कम हो, वह हीना चाहिए।

(iii) विशेष मामलों में जिन कर्मचारियों की 15 वर्ष की अवधि में सेवा की प्रतिक्रिया के लिए उन्हें 15 वर्ष की सेवा पूरी करने के पश्चात दकाया राशि को अविस्तर—आहरण में परिवर्तित करने को अनुमत किया जा सकता है।

(iv) वे कर्मचारी जिन्हें उपर्युक्त (iii) के अनुसार अप्रियम अनुमत किया गया है उन्हें 15 वर्ष की सेवा पूरी करने के पश्चात दकाया राशि को अविस्तर—आहरण में परिवर्तित करने को अनुमत किया जा सकता है।

(v) उक्त आहरण के बाद ही अनुमत होगा।

(ख) जिन कर्मचारियों ने 25 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है या जिन्हें अधिकारियों की प्रायः पूरी करने में भी अधिक से कम है, उन्हें निम्नलिखित शर्तों के अधीन उनकी मोटर गाड़ियों की व्यापक मरम्मत या शोबरत्तान के लिए भविष्य निधि याने से आङ्गण करने के लिए अनुमत किया जा सकता है :

(i) वे कर्मचारी जिनका वेतन 1400/- रुपए के समकक्ष है।

(ii) आहरण की अधिकतम मीमा राशि 5000/- रुपए है या अभिदाना के नाम भविष्य निधि आते में जमा राशि की एक तिहाई राशि या मरम्मत या शोबरत्तान की वास्तविक राशि, जो भी कम हो।

(iii) आहरण करते समय कार की खरीद के समय से पांच अर्ध वर्ष जाने चाहिए। पुरानी कार के मामले में प्रथम खरीदार द्वारा प्रारंभिक खरीद की तारीख को ध्यान में रखा जाएगा।

(iv) इस प्रशार का आहरण अधिदाता को पूरे सेवा काल में केवल एक बार अनुमत होगा।

(g) जिन कर्मचारियों ने 15 वर्ष की सेवा (खड़ित सेवा काल को मिलाकर यदि कोई हो) पूरी कर ली है उन्हें भवित्य निधि से आदिक साइकिल/ मोटरकार/मोटर साइकिल/ स्कूटर/मोपेड आदि की बुकिंग के लिए निम्नलिखित शर्तों के साथ, अनुमत किया जा सकता है:

(i) कर्मचारियों का मूल वेतन केन्द्रीय सरकार के वेतनमानों में 3500/- रुपए के समकक्ष मोटरकार के लिए और 1500/- रुपए मोटर साइकिल/ स्कूटर के लिए होना चाहिए।

(ii) आहरण की राशि की सीमा मोटरकार के लिए 10000/- रुपए और मोटर साइकिल/स्कूटर आदि के लिए 500/- रुपए है या अधिदाता के माम सामान्य भवित्य निधि में जमा राशि की 50 प्रतिशत राशि या मोटर साइकिल/स्कूटर आदि के मामलों में रजिस्ट्रेशन की वास्तविक राशि जो भी कम हो ;

(iii) कार, या मोटर साइकिल या स्कूटर आदि की बुकिंग के लिए अपेक्षित राशि के आहरण की राशि अधिक नहीं होगी।

(iv) आहरण की तारीख से एक माह के भीतर संबंधित प्रणालीनिक अधिकारी द्वारा जांच के लिए जमा रसीद प्रस्तुत कर देनी चाहिए। ऐसा न करने पर आहरण की कुल राशि वापिस करली पड़ सकती है।

(v) यदि कर्मचारी कार/मोटर साइकिल/ स्कूटर आदि नहीं खरीदता है या योजना से अलग हो जाता है तो उसे तत्काल अंतिम आहरण की राशि विनिर्वाता/डीलर से प्राप्त व्याज सहित भवित्य निधि खाते में जमा करानी चाहिए।

1	2	3	4	5
			(vi) विशेष मामलों में, यदि 15 वर्ष की त्यूनतम सेवा में 6 मही की अवधि कम होती है तो 36 किए भी अमूला जाते वाला प्रग्राम मंजूर विया जा सकता है और इस प्रकार मंजूर किया गया प्रग्राम 15 वर्ष की सेवा अवधि पूरी होने पर आंशिक अनिम आहरण में परिवर्तित किया जा सकता है।	
			(vii) इस प्रकार का आहरण केवल एक बार ही अनुमत होगा और गमान्य भविष्य निधि में से आहरण के लिए वर्तमान में विहित समग्र सीमा के अधीन होगा।	
			“(6) जब अभियाता नवीनतम अपमान विवरण और सत्यप्रतात किए गए अभिदान की राशि के संदर्भ में सामान्य अवधि जाने में अपने नाम में जमा/राशि के बारे में सक्षम प्राधिकारी को संतुष्ट कर देता है तो समय प्राधिकारी वापिस किए जाने वाले अधिस के मामलों की भाँति ही, विहित सीमाओं के भीतर, स्वयं आहरण मंजूर कर सकता है। ऐसा करते समय सक्षम प्राधिकारी अभिदाता को पहले मंजूर किए गए आहरणों या वापिस किए जाने वाले अधिसों को द्यान में रखेगा। ऐसे मामलों में, जहां अभियाता अपने नाम जमा राशि के बारे में सक्षम प्राधिकारी को संतुष्ट नहीं कर पाता है या भाँगी गई राशि को स्वीकारता के बारे में कोई संदेह है, तो सक्षम प्राधिकारी को लेखा अधिकारी को सूचित करके अभिदाता के नाम जमा राशि के बारे में पना लगा देना चाहिए ताकि आहरण की राशि की स्वीकार्यता निर्धारित की जा सके। आहरण की मंजूरी में प्रमुख रूप से सामान्य भविष्य निधि लेखा संस्था दी जानी चाहिए और उसकी प्रतिनिधि प्रनिवार्य रूप से लेखा अधिकारी को पृष्ठोक्ति की जानी चाहिए। यदि लेखा अधिकारी गूचित करता है कि आहरण की मंजूर की गई राशि अभियाता के नाम जमा राशि से अधिक है या अस्वीकार्य है तो अभियाता तत्काल निकाली गई राशि को एकमुग्ध रूप में निधि में वापिस जमा करेगा और ऐसा न करने पर मंजूरीदाता प्राधिकारी जैसा भी अध्यक्ष निर्धारित करे अभिदाता की परिलक्षियों में से एकमुग्ध रूप में या भासिक किश्तों में काटने के आदेश देगा।	

1

2

3

4

5

13. विनियम 18

18. आहरण की शर्तेः—

निधि में अपने नाम जमा राशि में से विनियम 17 में विनिर्दिष्ट एक या अधिक प्रयोजनों के लिए, किसी भी समय अभिदाता द्वारा निकाली गई राशि साधारणतया जमा राशि के आधु से या छह माह के बीतन से अधिक जो भी कम हो, नहीं होगी। तथापि भंजूरीदाता प्रधिकारी निम्न-तिथित बोतों को ध्यान में रखते हुए, निधि में जमा राशि में से इस सीमा से अधिक यथा जमा राशि के तीन चौथाई तक निकालने की भंजूरी दे सकता है।

- (i) प्रयोजन जिसके लिए आहरण किया जा रहा है।
- (ii) अभिदाता की हैमियत ; और
- (iii) निधि में उसके नाम जमा राशि।

“परंतु किसी भी मामले में विनियम 17 के अधीन उप विनियम 2 में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए आहरण मकान निर्माण के लिए अग्रिम भंजूर करने के लिए नव मंगलौर पत्तन न्यास कर्मचारी (मकान निर्माण के लिए अग्रिम की भंजूरी) विनियम 1980 के विनियम 4, 5 और 6 के अधीन समय-समय पर विहित अधिकतम सीमा से, अधिक नहीं होगा।

“परंतु अभिदाता ने यदि नव मंगलौर पत्तन न्यास कर्मचारी (मकान निर्माण के लिए अग्रिम की भंजूरी) विनियम 1980 के अधीन अग्रिम ले रखा है या किसी अन्य अनुमोदित योजना के अधीन अग्रिम ले रखा तो इस उप विनियम के अधीन निकाली गई राशि उपर्युक्त स्त्रोत से प्राप्त अग्रिम राशि को मिलाकर नव मंगलौर पत्तन न्यास कर्मचारी (मकान निर्माण के लिए अग्रिम की भंजूरी) विनियम, 1980 में समय-समय पर निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक नहीं होगी।

“टिप्पणी—विनियम 17 के उप विनियम 2 की उप धारा (क) के अधीन भंजूर आहरण की राशि किश्तों में निकाली जा सकती है। किश्तों की संख्या एक कैलेंडर वर्ष में चार से अधिक नहीं होगी और इनकी गणना भंजूरी की तारीख से की जाएगी।

टिप्पणी:—ऐसे मामले में, जब अभिदाता को ब्रह्मीदे गए भू-स्थल या मकान या फ्लैट के लिए या भारत सरकार द्वारा अनुमोदित विभिन्न योजनाओं या मकान निर्माण महकारी मिमिति के माध्यम से निर्मित मकान या फ्लैट के लिए किश्तों में अदायगी करनी है, तो जब कभी अदायगी के लिए उसे कहा जाएगा उसे किश्तों में आहरण करने की अनुमति दी जाएगी। नियम 16 के उपनियम 1 के प्रयोजन के लिए प्रत्येक इस प्रकार की अदायगी एक अलग प्रयोजन के लिए प्रदायगी समझी जाएगी।

(2) जिस अभिदाता को विनियम 17 के अधीन राशि निकालने की मंजूरी दी गई है वह मंजूरीदाता प्राधिकारी द्वारा निर्धारित उचित अवधि में इस भात से उसे संतुष्ट करेगा कि निकाली गई राशि उसी प्रयोजन के लिए उपयोग में पाई गई है जिसके लिए वह मंजूर की गई थी। ऐसा न करने पर निकाली गई भरती सारी या उसका वह भाग जो उस प्रयोजन के लिए उपयोग में नहीं लाया गया है जिसके लिए यह निकाली गई थी, तो अभिदाता को, तस्काल विनियम 12 के अधीन निर्धारित व्याज सहित, एकमुक्त रूप में भरती राशि निधि को लौटानी पड़ेगी और ऐसा न करने पर मंजूरीदाता प्राधिकारी अभिदाता की परिलक्षियों में से, प्रध्यक्ष द्वारा निर्धारित विधि में या तो एकमुक्त रूप में या मासिक किश्तों में काटने का आदेश देगा।

“परन्तु इस उप विनियम के अधीन आहरण की वापसी लागू करने में पहले, अभिदाता को इस प्रकार की सूचना मिलते कि “आहरण की वापसी अगो न लागू की जाए” के 15 विधि के भीतर निर्धारित रूप में अपना स्पष्टीकरण देने का अवसर दिया जाएगा और यदि मंजूरीदाता प्राधिकारी इस प्रकार किए स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं होता है

या उक्त पंचम दिन की अवधि में अभिदाता कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं करता है तो मंजूरी-दाता प्राधिकारी इस उपविनियम में किंवदं में राणि की वापसी को लाए करेगा।"

(3) जिस अभिवादा को विनियम 17 के विनियम 2 के अधीन निधि में से जमा राणि में से आहरण करने की मंजूरी दी गई है वह उस राणि से बनाए गए मकान या घरीदे गए गृह-स्थल को अपने कड़ों में रखेगा और मंजूरीदाता प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना, न तो उसे बेचेगा, न बंधक (मंजूरीदाता प्राधिकारी के पास बंधक रखने के अलावा) रखेगा और न ही उपहार में देगा। साथ ही मंजूरीदाता प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना उक्त मकान या गृह-स्थल को तीन वर्ष की अवधि से अधिक समय के लिए विनियम या पट्टे के स्पष्ट में देगा और उस पर अपना कड़ा बनाए रखेगा। अभिदाता प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर तक इस आण्य का घोषणा पत्र प्रस्तुत करेगा कि मकान या गृह-स्थल जो भी हो, वह उसके कड़ों में है या बंधक रख दिया गया है या अन्यथा हस्तान्तरित कर दिया गया है और यदि अपेक्षित हुआ तो मंजूरी-दाता प्राधिकारी द्वारा निर्धारित तिथि पर या उससे पहले उक्त सम्पत्ति पर अपने हक्क संबंधी मूल विक्रय विनेक पर अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करेगा।

जिस अभिवादा को विनियम 17 के विनियम 2 के अधीन निधि में से जमा राणि में से आहरण करने की मंजूरी दी गई है वह उस राणि से बनाए गए मकान या घरीदे गए गृह-स्थल को अपने कड़ों में रखेगा और (मंजूरीदाता प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना, न तो उसे बेचेगा, न बंधक (मंजूरीदाता प्राधिकारी के पास बंधक रखने के अलावा) रखेगा और न ही उपहार में देगा। साथ ही मंजूरीदाता प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना उक्त मकान या गृह-स्थल को तीन वर्ष की अवधि से अधिक समय के लिए विनियम या पट्टे के स्पष्ट में देगा और उस पर अपना कड़ा बनाए रखेगा। अभिदाता प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर तक इस आण्य का घोषणा प्रस्तुत करेगा कि मकान या गृह-स्थल जो भी हो, वह उसके कड़ों में है या बंधक रख दिया गया है या अन्यथा हस्तान्तरित कर दिया गया है या यथापूर्वोक्त पट्टे पर दिया गया है और यदि अपेक्षित हुआ तो मंजूरीदाता प्राधिकारी द्वारा निर्धारित तिथि पर या उससे पहले उक्त सम्पत्ति पर अपने हक्क संबंधी मूल विक्रय विनेक और अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करेगा।

"परन्तु आवासीय बोई राष्ट्रीयकृत यैक, जीवन बीमा निगम या केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में कोई अन्य नियम जो एग मकान के नियमण के लिए या विद्यमान मकान में परिवर्तन व परिवर्षन करने के लिए प्रग्राम बहु व्रान करते हैं, यदि उनके पास बंधक रखा जाना है तो उक्त अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।

1

2

3

4

5

13. विनियम 18

(4) यदि अभिदाता सेवा निवृत्ति से पूर्व किसी मंजूरीदाता को पूर्व मंजूरी के बिना मकान या गृह स्थल पर से अपना कब्जा छोड़ देता है, तो उसे निधि में से निकाली गई राशि निधि में एक मुश्त रूप में तुरन्त लौटानी होगी और ऐसा न करने पर मंजूरी-दाता प्राधिकारी अभियाता की परिनिधियों में से बोई द्वारा निर्धारित विधि से या तो एकमुश्त रूप में या मासिक किस्तों में काटने के आदेश देना।

(4) यदि अभिदाता सेवा निवृत्ति से पूर्व किसी सभ्य मंजूरीदाता की पूर्व मंजूरी के बिना मकान या गृह-स्थल पर से अपना कब्जा छोड़ देता है, तो उसे निधि में से निकाली गई राशि निधि में एकमुश्त रूप में तुरन्त लौटानी होगी और ऐसा न करने पर, अभियाता को इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण देने का पर्याप्त अवसर प्रदान करने के पश्चात, मंजूरीदाता प्राधिकारी अभियाता की परिनिधियों में से बोई द्वारा निर्धारित विधि से या तो एकमुश्त रूप में या मासिक किस्तों में काटने के आदेश देंगा।

(टिप्पणी) : यदि अभियाता ने नव मंगलोर पत्तन न्यास से अहं सिया है और उसके एवज में पत्तन न्यास बोई के पास या गृह-स्थल बंधक रखा है तो उसे निम्नलिखित रूप में घोषणा करनी पड़ेगी यथा:—

“मैं प्रमाणित करता हूं कि जिस मकान या गृह-स्थल के निर्माण या मंजून के लिए मैंने अधिक निधि से अंतिम आहरण लिया है वह मेरे कठजे में है लेकिन वह पत्तन न्यास बोई के पास बंधक रखा हुआ है।

(5) अभियाता को किसी भी स्थान पर मकान निर्माण के लिए दूसरा आहरण मंजूर नहीं किया जाना चाहिए, यदि उसे पहले ही उसी या सभ्य स्थल पर इसी प्रयोजन के लिए अंतिम आहरण मंजूर किया जा चुका है। अस्य शब्दों में, अंतिम आहरण एक से अधिक मकान के लिए नहीं दिया जाना चाहिए।”

14. विनियम 19

19. अग्रिम राशि को आहरण में परिवर्तित करना :

यदि अभियाता ने विनियम 17 के उप-विनियम (1) की उपधारा (अ) और (ग) में विनियमित किसी प्रयोजन के लिए विनियम 14 के प्रधान अग्रिम राशि विकाल रखी है या बाद में निकालना है तो वही अपने विकल्प पर, विनियम 17 और 18 में वी गई शर्तों को पूरा करते हुए मंजूरीदाता प्राधिकारी के माध्यम से लेखा अधिकारी को लिखित आवेदन करके शब्द बनाया राशि को अंतिम आहरण में परिवर्तित करा सकता है।

19. अग्रिम राशि को आहरण में परिवर्तित करना :

यदि अभियाता ने विनियम 17 के उप-विनियम (1) से (4) में विनियमित किसी प्रयोजन के लिए विनियम 14 के प्रधान अग्रिम राशि विकल्प पर, विनियम 17 और 18 में वी गई शर्तों को पूरा करते हुए मंजूरी-दाता प्राधिकारी के माध्यम से लेखा अधिकारी को लिखित आवेदन करके अंतिम आहरण में परिवर्तित करा सकता है।

1 2

3

4

5

टिप्पण : नियम 17 के उप विनियम 1 के प्रयोजन के लिए संपर्कशीलता के समय अधिकारी के नाम नभा ब्याज सहित अधिकारी की राशि और अधिक बकाया राशि को मिलाकर शेष राशि माना जाएगा । प्रदेशीक आहरण की एक भ्रलग मामला माना जाएगा और यही नियम एक से अधिक आहरणों पर भी लागू होगा ।

#### फार्म IX-क

(विनियम 39)

अधिक राशि को अंतिम आहरण में परिवर्तित करने के लिए आवेदन-पत्र का फार्म :

1. अधिकारी का नाम :

2. पद और कार्यालय का नाम :

3. बेतन

4. भविष्य निधि का नाम और जाता संदेश :

5. आवेदन करने की तारीख : पूर्ण इतिहास (सा.भ.नि. अधिकारी के मामले में वास्तविक रूप से दी गई अधिकारी की राशि उपर ब्याज सहित) ।

6. (क) बकाया शेष राशि जिसे अंतिम आहरण में परिवर्तित करना है ।

(ख) प्राप्त अधिक राशि पर देय ब्याज :

7. (क) अधिक सेने का प्रयोजन :

(ख) अधिक को अदायगी की तारीख

(ग) मंजूर अधिक की राशि :

8. अधिक को मंजूर करने का पूर्ण व्यौरा :

9. क्या कभी पहले उपर्युक्त उल्लिखित प्रयोजन के लिए कोई अधिक या अतिम आहरण लिया गया है, यदि हाँ, तो उसका विवरण

30. (क) आवेदन की तारीख पर कुल सेवा काल, बंडित सेवा काल को मिलाकर

(ख) आवेदन की तारीख पर अधिकारी की आयु प्राप्त में बाही क्षमी सेवा अवधि

(ग) अधिकारी की तारीख :

स्थान :

तारीख :

आवेदन को हस्ताक्षर

1 2

3

4

5

सं . . . . . तारीख . . . . .  
 उपर्युक्त विवरण जांच के पश्चात ठीक  
 पाए गए।

मिकार्पण करने वाले अधिकारी के  
 हस्ताक्षर एवं पद नाम

आदेश

सं . . . . . तारीख . . . . .

नव संगलीर पत्तन न्यास (सा.भ.नि. 11)  
 विनियम, 1980 के नियम 19 के अंतर्गत  
 कार्यालय के श्री/श्रीमती/  
 कुमारी 2 . . . . . को (प्रयोजन)  
 . . . . . के लिए 49 . . . . . को  
 मंजूर तथा बिल मंज्या . . . . . द्वारा  
 निकाली सामान्य भविष्य निधि मंदिर  
 की बकाया राशि 8 . . . . .  
 (सा.ये . . . . .) का  
 अंतिम प्राप्तरण में परिवर्तित करने के  
 लिए एतद्वारा . . . . . की  
 मंजूरी की जाती है।

(सामान्य भविष्य निधि खाता में . . . . .)

हस्ताक्षर

पदनाम

तारीख

सं:

प्रसिद्धि प्रेषितः

(1)'

(ii)

(iii)

आदि, आदि

हस्ताक्षर . . . . .

पदनाम

15. विनियम 27

27. वैयक्तिक सामग्री में उपबंधों और काट विया गया  
 विनियमों की छूट : जब शोर्ड संतुष्ट हो कि  
 इन विनियमों को लागू करने से अभिवाता को प्रनुचित कष्ट पहुंचता है या]  
 पहुंच सकता है तो शोर्ड, इन विनियमों में कोई भी प्राप्तवान होने क्षुण्ड भी,  
 ऐसे अभिवाताओं के मामले में,  
 इस प्रकार की कार्रवाही करेगा, जो  
 उचित और न्यास संगत हो।

1

2

3

4

5

16. विनियम 28

28. भारत में अभिवान की प्रदायरी करने समय, जाहे परिवर्त्यियों में से कटौती हो या नववरूप में, लेखा संख्या दी जानी चाहिए। अभिवाता निधि में अपने लेखे की संख्या देगा जो उसे लेखा अधिकारी सूचित करेगा। इसी प्रकार, यदि लेखा संख्या में कोई परिवर्तन होता है तो लेखा अधिकारी अभिवाता को सूचित करेगा।

17. विनियम 29

29.

28

18. विनियम 30

30. निषेध सहबद बीमा योजना : अभिवाता की मृत्यु हो जाने पर अभिवाता के नाम जमा राशि को प्राप्त करने के हकादार व्यक्ति को लेखा अधिकारी, निम्नलिखित गतों के साथ, अभिवाता की मृत्यु के तत्काल पूर्ववर्ती तीन बद्धों को औसत शेष राशि के बराबर अतिरिक्त राशि प्रदान करेगा,

(क) उक्त अभिवाता के नाम जमा शेष राशि मृत्यु के माह के पूर्ववर्ती तीन बद्धों में निम्नलिखित सीमा से कम नहीं होनी चाहिए :—

(i) 4000/- रुपए उस अभिवाता के मामले में, जो उपर्युक्त तीन बद्ध की अवधि के दौरान अधिक समय तक उस पद का धारक था जिसका अधिकात्म बेतनमान 1300/- रुपए या अधिक सेकिन 1300/- रुपए से कम था,

(ii) 2300 रुपए अभिवाता के मामले में जो उपर्युक्त तीन बद्ध की अवधि के दौरान अधिक समय तक पद का धारक था जिसका अधिकात्म बेतनमान 900/- रुपए या अधिक सेकिन 1300/- रुपए से कम था।

27. भारत में अभिवान की अदायरी करने समय, जाहे परिवर्त्यियों में से कटौती हो या नववरूप में, लेखा संख्या दी जानी चाहिए। अभिवाता निधि में अपने लेखे की संख्या देगा जो उसे लेखा अधिकारी सूचित करेगा। इसी प्रकार, यदि लेखा संख्या में कोई परिवर्तन होता है तो लेखा अधिकारी अभिवाता को सूचित करेगा।

29

30. निषेध सहबद बीमा योजना : अभिवाता की मृत्यु हो जाने पर अभिवाता के नाम जमा राशि को प्राप्त करने के हकादार व्यक्ति को लेखा अधिकारी, निम्नलिखित गतों के साथ, अभिवाता की मृत्यु के तत्काल पूर्ववर्ती तीन बद्धों को औसत शेष राशि के बराबर अतिरिक्त राशि प्रदान करेगा,

(क) उक्त अभिवाता के नाम जमा शेष राशि मृत्यु के माह के पूर्ववर्ती तीन बद्धों में निम्नलिखित सीमा से कम नहीं होनी चाहिए :—

(ii) 2500/- रुपए उस अभिवाता के मामले में जो उपर्युक्त तीन बद्ध की अवधि के दौरान अधिक समय तक उस पद का धारक था जिसका अधिकात्म बेतनमान 900/- रुपए या अधिक सेकिन 1300 रु. से कम था।

टिप्पण 1 से 4

टिप्पण 1 से 4

टिप्पण 5 : इस योजना से संबंधित व्यय के बजट प्राप्तकर्तन लेखा अधिकारी द्वारा व्यय की प्रवृत्तियों को व्यान में रखकर उसी रीति से बनाए जायेंगे जैसे अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभों के लिए बनाए जाते हैं।

19. विनियम 31

31

30

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT  
(Ports Wing)  
NOTIFICATION

New Delhi, the 16th December, 1991

G.S.R. 739(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (i) of section 124, read with sub-section (i) of section 132 of the Major Ports Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves New Mangalore Port Trust Employees (General Provident Fund) Regulations, 1991 made by the Board of Trustees for the Port of New Mangalore and set out in the Schedule annexed to this notification.

2. The said regulations shall come into force on the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[No. PR-12016/10/91-PE-1]

ASHOKE JOSHI, Jt. Secy.

NEW MANGALORE PORT TRUST EMPLOYEES  
(GENERAL PROVIDENT FUND) FIRST AMEND-  
MENT REGULATION, 1991. ।

In exercise of the powers conferred by Section 28 of the Major Port Trusts Act 1963 (38 of 1963) the New Mangalore Port Trust Board hereby makes, subject to the approval of the Central Government, under Section 124 of the above Act, the following Regulations to amend the New Mangalore Port Trust Employees (General Provident Fund) Regulations, 1980 (published as GSR 157(E) in the Gazette of India, Extraordinary dated 28th March, 1980 namely :—

1. (i) These Regulations may be called New Mangalore Port Trust Employees (General Provident Fund) Regulations first Amendment Regulations, 1991.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the New Mangalore Port Trust (General Provident Fund) Regulations, 1980 (hereinafter referred to as the said Regulations). In Regulation 2 of the said regulations, add the following at the end of sub-clause (i) as well as sub-clause of sub-regulation (e).

“Minor Brothers, unmarried sisters and parents and where no parents of the subscriber is alive, a paternal grand parent.”

3. In Regulation 4 of the said Regulations the sub-regulation 4 shall be deleted and sub-regulations 5 & 6 shall be renumbered as 4 and 5 respectively. The following shall be inserted as sub-regulation 6.

6. “Apprentice and probationers shall be treated as temporary Government servants for the purpose of this Rule.”

4. In regulation No. 6 of the said Regulations under the sub-regulation No. 1 the following first proviso shall be inserted before the existing provision :

“Provided that when a subscriber is a minor, he shall be required to make the nomination only on his attaining the age of majority.”

The first and second provisos under this sub-regulation shall be read as second and third proviso.

The following note shall be inserted under the regulation :

“Note : In this rule, unless the context otherwise requires “person” or “persons” shall include a company or association or body of individuals, whether incorporated or not. It shall also include a fund such as the Prime Minister’s National Relief fund or any charitable or other trust or fund, to which nomination may be made through the Secretary, or other executive authorised to receive payment.”

5. The Regulation No. 7 of the said regulations shall be modified as follows :

“7. Subscribers Account, An account shall be opened in the name of each subscriber in which shall be shown :

- (i) his subscriptions.
- (ii) interest, as provided by rule 12 on subscription.
- (iii) advances and withdrawal from the fund.”

6. In Regulation No. 8 of the said regulations under the sub-regulation No. (1) the following note shall be inserted :

“Note :—A subscriber need not subscribe during a period treated as “dies non”.

The following sub-regulation shall be added as sub-Regulation No. (3) and (4) under the regulation :

“(3) A subscriber who has under rule 21 withdrawn the amount standing to his credit in the fund shall not subscribe to the fund after such withdrawal unless he returns to duty.”

“(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) a subscriber shall not subscribe to the fund for the month in which he quits service unless, before the commencement of the said month, he communicates for the Head of office in writing his option to subscribe for the said month.”

In Regulation 8 the following shall be added as sub-regulations (5) & (6):

(5) “An employee due to retire on superannuation shall be exempted from making any subscription to the Fund during the last 3 months of his service. The discontinuance of subscription would compulsory and not ‘optional’.”

(6) “Such of the subscriber as are entitled to PLB or performance reward, may, if they so desire, deposit the whole or part of the amount admissible under the scheme in their respective Provident Fund A/C.”

7. In Regulation 9 of the said regulations, the proviso (i) under the sub-clause (a) of sub-regulation (2) shall be modified as follows :

“(1) If the subscriber was on leave on the said date and elected not to subscribe during such leave or was under suspension on the said date, his emoluments shall be the emoluments to which he was entitled on the first day after his return to duty.”

8. In regulation 12 of this regulation the proviso 1 under sub regulation 1 the percentage of interest occurring in the 2nd, 3rd and 4th line shall be read as 8 per cent instead of 4 per cent.

In Regulation No. 12 of the said regulation under sub-regulation 4 the following 2nd proviso shall be inserted under the existing proviso :

“Provided further that where a subscriber on deputation to a body corporate, owned or controlled by the Government or an autonomous organisation registered under the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860) is subsequently absorbed in such body corporate or organisation with effect from a retrospective date, for the purpose of calculating the interest due on the fund accumulations of the subscriber the date of issue of the orders regarding absorption shall be deemed to be the date on which the amount to the credit of the subscriber becomes payable subject, however, to the condition that the amount recovered as subscription during the period commencing from the date of absorption and ending with the date of issue of order of absorption shall be deemed to be subscription to the fund only for the purpose of awarding interest under this sub-regulation.”

The following sub-regulation shall be added under regulation as sub-regulation Nos. 6 and 7.

“6 The interest on amounts which under sub-regulation (3) of regulation 11, regulation 21 or regulation 22 are replaced to the subscriber in fund, shall be calculated at such rates as may be successively prescribed under sub-rule (1) of this regulation and so far as may be in the manner described in this regulation.”

“7 In case a subscriber is found to have drawn from the fund an amount in excess of the amount standing to his credit on the date of the drawal, the overdrawn amount, irrespective of whether the overdrawal occurred in the course of an advance or a withdrawal or the final payment from the fund, shall be repaid by him with interest thereon in one lumpsum, or in default be ordered to be recovered by deduction in one lumpsum from the emoluments of the subscriber. If the total amount to be recovered is more than half of the subscribers emoluments, recoveries may be made in monthly instalments of moiety of his emoluments till the entire amount together with interest is recovered.”

9. The regulation No. 13 of the said regulations shall be deleted.

10. In regulation No. 14 under the said regulations, sub-regulation 1(d) shall be modified as follows :

“(d) to meet the cost of legal proceedings instituted by or against the subscriber, any member of his family or any person actually dependent on him, the advance in this case being available in addition to any advance admissible for the same purpose from any other source (Port).”

The following shall be added as sub-regulation No. 4 under the regulation.

4 when an advance is sanctioned under sub-rule (2) before repayment of last instalment of any previous advance is completed the balance of any previous advance not recovered shall be added to the advance so sanctioned and the instalments for recovery shall be fixed with reference to the consolidated amount.”

In regulation 14 of the said regulations, add the following as sub-regulation (5).

5) “No temporary advance shall be sanctioned during the last 3 months of service in order to enable the Accounts Officer to complete the task of issuing authority for payment one month before the retirement.” The proforma for “application for advance from Provident Fund” Form No VI shall be substituted by the form attached.

11. In Regulation No. 15 under the said regulation, the following proviso shall be inserted under sub-regulation No. (3) :

“Provided that, before such advance is disallowed, the subscriber shall be given an opportunity to explain to the sanctioning authority in writing and within fifteen days of the receipt of the communication why the repayment should not be enforced and if any explanation is submitted by the subscriber within the said period of fifteen days it shall be referred to the Chairman for decision and if no explanation within the said period is submitted by him, the repayment shall be enforced in the manner prescribed in this sub-rule.”

12. The Regulation No. 16 of the said regulations shall be modified as under :

16. Wrongful use of advance.—notwithstanding anything contained in this regulation, if the sanctioning authority has reason to doubt that money drawn as advance from the fund under Rule 14 has been utilised for a purpose other than that for which sanction was given to the drawal of the money, he shall communicate to the subscriber the reason for his doubt and require him to explain in writing and within fifteen days of the receipt of such communication whether the advance has been utilised for the purpose for which sanction was given to the drawal of the money. If the sanctioning authority is not satisfied with the explanation furnished by

the subscriber within the said period of fifteen days, the sanctioning authority shall direct the subscriber to repay the amount in question to the fund forthwith or, in default, order the amount to be recovered by deduction in one lumpsum from the emoluments of the subscriber even if he be on leave. If however, the total amount to be repaid be more than half the subscribers emoluments, recoveries shall be made in monthly instalments of moiety of his emoluments till the entire amount is repaid by him."

Note :—The terms "emoluments" in the rule does not include subsistence grant

13. In Regulation No. 17, under the said regulations, the first four lines of sub-regulation No. (2) shall be modified as follows :

"(2) After the completion of (ten years) of service (including broken periods of service if any) of a subscriber or within ten years before the date of his retirement on superannuation, whichever is earlier, from the amount standing to his credit in the fund for one or more of the following purposes, namely;

Add the following under sub-regulation (2) as sub-clause (c) renumbering the existing sub-clause as sub-clause (d) under the regulation :

(c) Renovating additions or alteration or up-keep of an ancestral house at a place other than the place of duty or to a house built with the assistance of loan from the NMPT at a place other than the place of duty."

Add the following sub-regulations (3) and (4) under the Regulation :

"(3) Within six months before the date of subscriber's retirement, from the amount standing to his credit in the fund for the purpose of acquiring a farm land or business premises or both."

"(4) Once during the course of a financial year, an amount equivalent to one year's subscription paid by the subscriber towards the Group Insurance Scheme for the employees organised by L.I.C. of India for N.M.P.T. on self financing and contributing basis."

Note 2 under the regulation shall be read as no'e 6 and the following inserted as Notes 1 to 5 :

"Note 1 : A subscriber who has availed himself of an advance under the N.M.T.P. for the grant of advance for house building purpose, or has been allowed any assistance in this regard from any other recognised housing scheme shall be eligible for the grant of withdrawal under sub-clause (a), (c), (d) of sub-regulation (2) of this regulation for the purpose specified therein and also for the purpose of repayment of any loan taken under the aforesaid scheme subject to the limit specified in the proviso to sub-rule (1) of rule 18.

If the subscriber has an ancestral house or built a house at a place other than the place of his duty with the assistance of loan taken from the Government he shall be eligible for the grant of a final withdrawal under this regulation for purchase of a house site or for construction of another house or for acquiring a ready built flat at the place of his duty.

Note 2 . Withdrawal under sub-clause (a), (c) and (d) of sub-regulation 2 of this regulation shall be sanctioned only after a subscriber has submitted a plan of the house to be constructed or of the addition or alteration to be made duly approved by the local municipal body of the area where the site or house is situated and only in case where the plan is actually got approved.

Note 3 : The amount of withdrawal sanctioned under for sub-clause (b) of sub-regulation 2 shall not exceed  $\frac{3}{4}$ th of the balance of date of application together with the amount of previous withdrawal under sub-clause (a) reduced by the amount of previous withdrawal, the formula to be followed is  $\frac{3}{4}$ th of (the balance as on date plus amount of previous withdrawal(s) for the house in question) minus the amount of previous withdrawal.

Note 4 : Withdrawal under sub-clause (a) of sub-regulation 2 shall also be allowed where the house site or home is in the name of wife or husband provided she or he is the first nominee to receive provident fund money in the nomination made by the subscriber.

Note 5 : Only one withdrawal shall be allowed for the same purpose under this rule. But marriage or education of different children or illness on different occasions or a further addition or alteration to the house or flat covered by fresh plan duly approved by the local municipal body of the area where the house or flat is situated shall not be treated as the same purpose. Second or subsequent withdrawal under sub-clause (a) or sub-clause (c) of sub-regulation 2 shall be allowed upto the limit laid down under Note 3.

Insert the following as Note No. 7 under sub-regulation (2)—

Note 7 : No partial final withdrawal may be permitted during the last 3 months of service. However in exceptional cases this may be permitted under the sanction of the Head of the department, impressing on the employee concerned the possibility of delay in the issue of authority for final withdrawal one month before the retirement.

The following shall be added as sub-regulation No. 5 :

"(5) In the following cases also part final/final withdrawals from the General Provident Fund are allowed."

(a) Employees who have completed 15 years of service (including broken period of service if any) or who have less than 5 years to attain the age of superannuation may be permitted to make part final withdrawals from their Provident Fund for purchasing Motor Car/Motor Cycle or Scooter etc. or for repay-

ing loan taken from the Port for this purpose subject to the following condition :

- (i) The employees' Basic pay should be the equivalent of Rs. 3,500/- P.M. in case of Motor Cycle|Scooter.
- (ii) The amount of withdrawals limited to Rs. 25,000/- for purchase of Motor Car and Rs. 4,000/- for the purchase of Motor Cycle|Scooter etc. Where the withdrawal has already been made for deposit for booking these vehicles the employees will be eligible for drawal of only the balance amount and also subject to the over all ceiling limit prescribed here. The total amount of withdrawal for this purpose (deposit for booking plus the amount required for purchase) should not exceed 50% of the amount standing to the credit of subscriber in the GPF account (including interest) on the date of withdrawal or the actual price of the vehicle whichever is less.
- (iii) In special cases an advance refundable in not more than 36 instalments in the case of employees who may fall short of the minimum service 15 years by a period not more than 6 months may be allowed by the Chairman.
- (iv) The employees who have been allowed advance according to (iii) above may be permitted to convert the outstanding balance of the advance into final withdrawal after completion of 15 years of service.
- (v) Such withdrawal shall be allowed only on one occasion.

(b) Employees who have completed 28 years of service or who have less than 3 years to attain the age of superannuation may be permitted to make final withdrawals from Provident Fund for extensive repair or overhauling of their Motor Cars subject to the following condition :

- (i) Employees whose pay is equivalent to Rs. 1,400/-.
- (ii) Amount of withdrawal is limited to Rs. 5,000 or 1/3rd of the amount standing to the credit of the subscriber in the G. P. Fund or the actual amount of repairing or overhauling whichever is the least.
- (iii) Not less than 5 years should have elapsed since the car was purchased. In case of second hand cars the initial date of purchase by the first purchaser will be taken into account.
- (iv) Such withdrawal shall be allowed only once in the service career of the subscriber.

(c) Employees who have completed 15 years of service (including broken period if any) may be permitted to make a partfinal withdrawal from the General Provident Fund for booking a Motor Car|Motor

Cycle|Scooter|Moped etc. subject to the following conditions :

- (i) The employees' basic should be equivalent Rs. 3,500/- for Motor Car and Rs. 1,500/- in case of Motor Cycle|Scooter etc.
- (ii) The amount of withdrawal is limited to Rs. 10,000 in the case of Car and Rs. 500 in the case of Motor Cycle|Scooter etc., or 50% of the amount standing to the credit of the subscriber in the G. P. Fund or the actual amount of registration in the case of Motor Cycle|Scooter etc. whichever is less.
- (iii) The amount of withdrawal shall not exceed the amount required for booking a car or Motor Cycle or Scooter etc.
- (iv) The deposit receipt must be produced for verification by the concerned administrative authority within a period of one month from the date of drawal. Failure to do so would involve refund of the total amount of withdrawal.
- (v) If the employee does not purchase a Car|Motor Cycle|Scooter etc. or gets out of the scheme he should immediately deposit the amount of final withdrawal together with interest received thereon from the manufacturer|dealer into the Provident Fund account.
- (vi) In special cases when the minimum service of 15 years falls short by six months, advance recoverable in 36 instalments may be sanctioned and this is eligible for conversion into part final withdrawal after completion of 15 years service.
- (vii) Such withdrawal shall be allowed only on one occasion and subject to overall ceiling at present prescribed for withdrawal in G.P. Fund.

The following shall be added as sub-regulation No. 6.

"(6) Whenever a subscriber is in a position to satisfy the competent authority about the amount standing to his credit in the General Provident Fund Account with reference to the latest available statement together with the evidence of subsequent contribution, the competent authority may itself sanction withdrawal within the prescribed limits, as in the case of refundable advance. In doing so, the competent authority shall take into account any withdrawal or refundable advance already sanctioned by it in favour of the subscriber. Where, however, the subscriber is not in a position to satisfy the competent authority about the amount standing to his credit or where there is any doubt about the admissibility of the withdrawal applied for, a reference may be made to the Accounts Officer by the competent authority for ascertaining the amount standing to the credit of the subscriber with a view to enable the competent authority to determine the admissibility of the amount of withdrawal. The sanction for the withdrawal should prominently

I indicate the General Provident Fund Account Number and a copy of the sanction should invariably be endorsed to the Accounts Officer. In case the Accounts Officer reports that withdrawal as sanctioned is in excess of the amount to the credit of the subscriber or otherwise inadmissible, the sums withdrawn by the subscriber shall forthwith be repaid in one lumpsum by the subscriber to the fund and in default of such repayment, it shall be ordered by the sanctioning authority to be recovered from his emoluments either in lumpsum or in such number of monthly instalments as may be determined by the Chairman.

14. In Regulation 18, under sub-regulation (1) of said Regulations, insert the following proviso and notes.

"Provided that in no case the maximum amount of withdrawal for purposes specified in sub-regulation 2 under regulation 17 shall exceed the maximum limit prescribed from time to time under regulation 4,5 and 6 of the New Mangalore Port Trust Employees (Grant of Advance for Building of House) Regulations 1980, for grant for house building purpose."

"Provided that in the case of subscriber who has availed himself of an advance under the N.M.P.T. Employees (Grant of Advances for Building of Houses) Regulations 1980 or has been allowed assistance from any other approved scheme the sum withdrawn under this sub-regulation together with the amount of advance taken under the above sources shall not exceed the maximum limit prescribed from time to time under the N.M.P.T. Employee (Grant of Advance for Building of Houses) Regulation 1980.

Note :—A withdrawal sanctioned to a subscriber under sub-clause (a) of sub-regulation 1 of regulation 17 may be drawn in instalments the number of which shall not exceed four in a period of twelve calendar months counter from the date of sanction.

Note 2 :—In case when a subscriber has to pay in instalments for a site or a house or flat purchased, or a house or flat constructed, through the various schemes approved by the Government of India or a House Building Co-operative Society he shall be permitted to make a withdrawal as and when he is called upon to make a payment in any instalment. Every such payment shall be treated as payment for a separate purpose for the purpose of sub-rule (2) of rule 17."

The following proviso shall be inserted under sub-regulation 2 under the regulation.

"Provided that, before repayment of a withdrawal is enforced under this sub-regulation, the subscriber shall be given an opportunity to explain in writing and

within fifteen days of the receipt of the communication why the repayment shall not be enforced, and if the sanctioning authority is not satisfied with the explanation or no explanation is submitted by the subscriber within the said period of fifteen days, the sanctioning authority shall enforce the repayment in the manner prescribed in this sub-regulation".

The following proviso shall be inserted under sub-regulation (3) under the regulation :

"Provided such permission shall not be necessary for its being mortgaged in favour of a Housing Board, Nationalised Bank, the Life Insurance Corporation or any other Corporation owned or controlled by the Central Government which advance loan for the construction of a new House or for making addition or alternation to an existing house".

In the last sentence of this sub-regulation the words "or let out as aforesaid" shall be inserted between the words "or otherwise transferred" and "and shall" and the words "mortgage or lease deed and also" shall be substituted for the words "deed and" occurring in the penultimate line.

In sub-regulation (4) the words "after giving the subscriber a reasonable opportunity of making a representation in the matter" shall be inserted between the words "such repayment" and "it shall be ordered" occurring in the fourth line.

The following Note shall be inserted under Regulation 18 of the said Regulation :

Note :—A subscriber who has taken a loan from the New Mangalore Port Trust and in lieu thereof mortgaged the house or house site to the Port Trust Board shall be required to furnish the declaration to the following effect, namely :—

I do hereby certify that the house or house site for the construction of which or for the acquisition of which I have taken a final withdrawal from the Provident Fund continues to be in my possession but stands mortgaged to the Port Trust Board."

The following shall be added as sub-regulation 5 under the regulation :

"(5) A subscriber should not be granted a second withdrawal for house building purposes at any place if he has already been granted a final withdrawal for similar purposes at the same or another place. In other words, final withdrawal should not be allowed for more than one house."

15. Insert the following as Note under regulation 19 under the said Regulation :

"Note :—For the purpose of sub-regulation 1 of rule 17 the amount of subscription with interest thereon standing to the credit of the subscriber in the account at the time of conversion plus the outstanding amount of advance shall be taken as the balance.

Each withdrawal shall be treated as a separate one and the same principle shall apply in the event of more than one conversion".

In regulation 19 of the said Regulation, the reference to "sub clause (b) and (c) of sub regulation (1)" shall be substituted by the words "sub regulation (1) to (4)."

The Form placed below shall be adopted as Form IX (A) Form of application for conversion of an Advance into a Final withdrawal."

16. In Regulation 27 of the said regulation, this regulation shall be deleted and regulation 28,29,30 and 31 shall be renumbered as 27,28,29 and 30 respectively.

17. In regulation 30, sub regulation (a) sub-clause (i) of the said Regulation's the amount Rs. 2300/- shall be substituted by the amount Rs. 2500/-

Note 5 shall be inserted under the Regulation :

"Note 5. The Budget estimates of expenditure in respect of this scheme will be prepared by the Accounts Officer having regard to the trend of expenditure, in the same manner as estimates are prepared for other retirement benefits."

Principal Regulations :

Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) Notification at GSR 157(E) dated 28th March 1980.

Administrative Office,  
New Mangalore Port Trust,  
Panambur, Mangalore-575010.  
(B. MAHAPATRA, Chairman)

**FORM IX-A (Regulation No. 19)**

Form of Application for conversion of an advance into a final withdrawal.

1. Name of the subscriber
2. Designation and Office to which attached.
3. Pay
4. Name of the Provident Fund and Account Number
5. Balance at credit on the date of application (amount actually subscribed by him alongwith interest due thereon in the case of GPF subscriber).
6. (a) Balance outstanding to be converted into a final withdrawal.  
(b) Interest due on the amount of advance taken.
7. (a) Purpose for which advance taken,  
(b) Date of payment of the advance  
(c) Amount of advance sanctioned.
8. Particulars of communication under which advance was sanctioned.
9. Whether any advance or final withdrawal has been drawn previously for the purpose mentioned above if so, particulars thereof.
10. (1) Total service, including broken periods, if any, on date of this application.  
(b) Period of service left on the date of application for attaining the age of superannuation.  
(c) The date of superannuation

Place:

Date:

No:

The above particulars have been verified to be correct.

Signature of the applicant

Dated

Signature and Designation of recommending authority.

## ORDER

No.

Dated....

Sanction of..... is hereby conveyed/accorded under Rule 19 of the New Mangalore Port Trust Employees (G.P.F.) Regulations, 1980 for the conversion into final withdrawal of an amount of Rs.....(Rupees.....only) being the outstanding balance out of the G.P.F. advance of Rs.....sanctioned on.....19.....and drawn in Bill No.....of .....for the (purpose).  
to Sri/Shrimathi/Kum.....  
of the office of the.....  
(G.P.F. Account No.....)

Signature.....

Designation.....

Date .....

No.

Copy forwarded to:

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

Signature .....

Designation.....

## FORM VI (Regulation 14)

Preference for application for advance from Provident Funds

New Mangalore Port Trust  
Department of...../Office.

Application of advance from.....

(Here enter the name of Fund)

1. Name of the subscriber
2. Account Number (with Departmental suffix)
3. Designation
4. Pay
5. Balance at credit of the subscriber on the date of application as below.

(i) Closing balance as per statement for the year Rs.

(ii) Credit from.....to.....on account of monthly subscription. Rs.

(iii) Refunds Rs.

(iv) withdrawals during the period from.....to..... Rs.

(v) Net balance at credit Rs.

6. Amount of advance/outstanding if any, and the purpose for which advance was taken by then.  
 Amount of advance taken Rs..... Balance outstanding as date Rs.....

7. Amount of advance required Rs.

8. (a) Purpose for which the advance is required.  
 (b) Rules under which the request is covered  
 (c) If advance is sought for House Building etc., following information may be given:-  
 (i) Location and measurement of the plot.  
 (ii) Whether plot is freehold or on lease.  
 (iii) Plan for construction  
 (iv) If the flat or plot being purchased is from a G.B. Society the name of the society, the location and measurements etc.,  
 (v) Cost of construction  
 (vi) If the purchase of flat is from DDA or any Housing Board, etc., the location dimension, etc. may be given

(d) If advance is required for education of children, following details may be given:-  
 (i) Name of the son/daughter  
 (ii) Class and Institution/College where studying  
 (iii) Whether a day-scholar or a hostler

(e) If advance is required for treatment of ailing family members, following detail may be given  
 (i) Name of the patient and relationship  
 (ii) Name of the Hospital/Dispensary/Doctor where the patient is undergoing treatment  
 (iii) Whether outdoor/indoor patient  
 (iv) Whether reimbursement available or not.

NOTE: In case of advance under 8(c) to 8(e), no certificate of documentary evidence would be required.

9. Amount of the consolidated advance (items 6 and 7 and number of monthly instalments in which the consolidated advance is proposed to be repaid) Rs..... in instalments.

10. Full particulars of the pecuniary circumstance of the subscriber, justifying the application for the advance.

I certify that particulars given above are correct and complete to the best of my knowledge and belief and that nothing has been concealed by me.

Dated :

Signature of Applicant

Name.....

Designation.....

Section/Branch.....

## Amendment to New Mangalore Port Trust Employees (General Provident Fund) Regulations 1980

## ANNEXURE-II

Sl. No.	Regulation to which Amendment is proposed	Original Provision in New Mangalore Port Employees (General Provident Fund) Regulation 1980	Amendment proposed	Justification
1	2	3	4	5
1.	Regulation 2	<p>Definitions:-</p> <p>(e) Family means—</p> <p>(i) In the case of a male Subscriber the wife or wives and children of a subscriber and the widow or widows and children of a deceased son of a subscriber.</p> <p>(ii) In the case of female subscriber, the husband and children of the subscriber and the widow or widow and children of a deceased son of a subscriber.</p>	<p>“Minor brothers, unmarried sisters and parents and where no parents of the subscriber is alive a paternal grand parent”.</p> <p>“Minor brothers, unmarried sisters and parents and where no parents of the subscriber is alive a paternal grand parent”.</p>	As provided for in CCS (GPF) Rules 1962
2.	Regulation 4	<p>4. Conditions of eligibility—</p> <p>(1) All temporary employees after a continuous service of one year, all re-employed pensioners other than those eligible for admission to the contributory provident fund and all permanent employees shall subscribe to the fund.</p> <p>(2) All temporary employees who complete one year of continuous service during the middle of the month shall subscribe to the fund from the subsequent month.</p> <p>(3) Temporary employees who have been appointed against regular vacancies and are likely to continue for more than a year may subscribe to the fund at any time before completion of one year's service</p> <p>(4) The Board, may, at its discretion require any other category of employee to subscribe to the fund.</p>	<p>4. Conditions of eligibility—</p> <p>1. All temporary employees after a continuous service of one year, all re-employed pensioners other than those eligible for admission to the contributory provident Fund shall subscribe to the fund.</p> <p>(2) All temporary employees who complete one year of continuous service during the middle of the month shall subscribe to the fund from the subsequent month.</p> <p>(3) Temporary employees who have been appointed, against regular vacancies and are likely to continue for more than a year may subscribe to the fund at any time before completion of one year's service</p> <p>(4) Employees who are subscribers to any contributory provident fund shall not be required to subscribe to the fund.</p>	<p>The suggestions made by the committee on sub-ordinate legislation of Rajya Sabha in their meeting held at Panambur in October 1990 as communicated by the Ministry of Surface Transport (Ports and all permanent employees Wing) in their letter No. PR-12016/10/91-PE.I dated 25-2-91.</p>

1 2

3

4

5

(5) Employees who are subscribers to any contributory provident fund shall not be required to subscribe to the fund.

(6) The procedure for admission of an employee to the fund shall involve the following namely:—

(a) Submission of an application form.

(b) Allotment of account number. The Head of the office shall obtain the application from the employees 3 months ahead of the officials completing one year of service; in Form 1.

### 3. Regulation 6

#### 6. Nomination :

(1) A subscriber shall at the time of joining the fund send to the Accounts Officer a nomination conferring on one or more persons the right to receive the amount that may stand to his credit in the fund in the event of his/her death, before the amount has become payable, or having become payable, has not been paid :

Provided that a subscriber, who has a family at the time of making the nomination shall make such nomination only in favour of a member or members of his family.

(5) The procedure for admission of an employee to the fund shall involve the following namely:—

(a) Submission of an application Form 1

(b) Allotment of Account number. The Head of the office shall obtain the application from the employees 3 months ahead of the officials completing one year of service; in Form 1

#### 6. Nomination :—

(1) A subscriber shall at the time of joining the fund send to the Accounts Officer a nomination conferring on one or more persons the right to receive the amount that may stand to his credit in the fund in the event of his/her death, before the amount has become payable, or having become payable, has not been paid;

“Provided that when a subscriber is a minor, he shall be required to make the nomination only on his attaining the age of majority”.

“Provided that a subscriber, who has a family at the time of making the nomination, shall make such nomination only in favour of a member or members of his family.

“Provided further that the nomination made by the subscriber in respect of any other Provident Fund to which he was subscribing before joining the fund shall, if the amount to his credit in such other fund has been transferred to his credit in the fund be deemed to be a nomination duly

1 2 3

4

5

made under this regulation until he makes a nomination in accordance with his regulation.

Note : In this rule, unless the context otherwise requires "Person" or "Persons" shall include a company or Association or body of individuals, whether incorporated or not. It shall also include a fund such as the Prime Minister's National Relief Fund or any charitable or other trust or fund to which nomination may be made through the Secretary, or other executive authorised to receive payment."

#### 4. Regulation

**7. Subscriber's Accounts :—**  
An account shall be maintained in the name of each subscriber and shall show the amount of his subscriptions with interest thereon calculated as prescribed in regulation 12 as well as advances and withdrawals from the fund.

**7. Subscribers Account :—** An account shall be opened in the name of each subscriber in which shall be shown :  
 (i) his subscriptions.  
 (ii) Interest, as provided by rule 12 on subscription.  
 (iii) Advances and withdrawal from the fund.

#### 5. Regulation 8

**8. Conditions and rates of Subscription :**

(i) A subscriber shall subscribe monthly to the fund except during the period when he is under suspension :

Provided that a subscriber may at his option, not subscribe during leave which either does not carry any leave salary leave or carries leave salary equal to or less than half pay :

Provided further that a subscriber on reinstatement after a period passed under suspension shall be allowed the option of paying in one sum or in instalments any sum not exceeding the maximum amount of arrears of subscription payable for the period of suspension.

1 2

3

4

5

“Note:—A subscriber need not subscribe during a period of dies non”

(2) A subscriber shall intimate in writing his election not to subscribe during leave (referred to in the first proviso to sub-regulation (1) of regulation 8 to the Accounts Officer. Failure to make due and timely intimation shall be deemed to constitute an election to subscribe. The option of a subscriber intimated under this sub-regulation shall be final.

(3) A subscriber who has under rule 21 withdrawn the amount standing to his credit in the fund shall not subscribe to the fund after such withdrawal unless he returns to duty”.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) a subscriber shall not subscribe to the fund for the month in which he quits service unless, before the commencement of the said month, he communicates to the head of office in writing his option to subscribe for the said month.

(5) An employee due to retire on superannuation shall be exempted from making any subscription to the fund during the last 8 months of his service. The discontinuance of subscription would be compulsory and not optional.

(6) Such of the subscribers as are entitled to PLB or Performance Reward may, if they so desire deposit the whole or part of the amount admissible under the scheme in their respective Provident Fund A/c.

#### 6. Regulation 9

#### 9. Rate of subscription—

(2)

(a)

Provided that

(i) If the subscriber was on leave and elected not to

(i) If the subscriber was on leave on the said date and

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

		subscribe during such leave on the said date his emoluments shall be the emoluments to which was entitled on the first day after his return to duty.	elected not to subscribe during such leave or was under suspension on the said date, his emoluments shall be the emoluments to which he was entitled on the first day after his returns to duty.	
7. Regulation 12		12. Interest—(1) Subject to the provisions of sub-regulation (5) the Board shall pay to the credit of the account of a subscriber interest at such rate as may be determined for each year by the Board:	12. Interest—(1) Subject to the provisions of sub-regulation (5) the Board shall pay to the credit of the account of a subscriber interest at such rate as may be determined for each year by the Board:	The suggestions made by the Committee on Sub-ordinate legislation of Rajyasabha in their meeting held at Panambur in October 1990 as communicated by the Ministry of Surface Transport (Ports Wing) in their letter No. PR-12016/10-91-PE.1 dated 25-2-1991.
		Provided that, if the rate of interest determined for a year is less than 4 per cent all subscribers to the fund in the year preceding that for which the rate has for the first time been fixed at less than 4 per cent shall be allowed interest at 4 per cent	Provided that, if the rate of interest determined for a year is less than 8 per cent all subscribers to the fund in the year preceding that for which the rate has for the first time been fixed at less than 8 per cent shall be allowed interest at 8 per cent.	
		(4) In addition to any amount to be paid under the regulation 21, 22 and 23 interest thereon upto end of the month preceding that in which the payment is made upto the end of the sixth month after the month in which such amount became payable, whichever of these periods be less, shall be payable to the person to whom such amount is to be paid:		
		Provided that where the Accounts Officer has intimated to that person (Or his agent) a date on which he is prepared to made in cash, or has posted a cheque in payment to that person interest shall be payable only upto the end of the month preceding the date so intimated or the date of posting the cheque as the case may be.		
			“Provided further that where a subscriber on deputation to a body corporate owned or	

1 2

3

4

5

controlled by the Government or an autonomous organisation registered under the Societies Registration Act 1860 (21 of 1860) is subsequently absorbed in such body corporate or organisation with effect from a retrospective date, for the purpose of calculating the interest due on the fund accumulations of the subscriber the date of issue of the orders regarding absorption shall be deemed to be the date on which the amount to the credit of the subscriber becomes payable subject, however, to the condition that the amount recovered as subscription during period commencing from the date of absorption and ending with the date of issue of order of absorption shall be deemed to be subscription to the fund only for the purpose of awarding interest under this sub-regulations.

5. xx xx

5. Interest shall not be credited to the accounts of a subscriber if he informs the accounts Officer that he does not wish to receive it; but if he subsequently asks for interest, it shall be credited with effect from the first day of the year in which he asks for it.

(6) The interest on amounts which under sub-regulation (3) of regulation 11 regulation 21 or regulation 22 are replaced to the subscriber in fund, shall be calculated at such rates as may be successively prescribed under Sub-Rule (1) of this regulation and so far as may be in the manner described in this regulation"

(7) In case a subscriber is found to have drawn from the fund an amount in excess of the amount standing to his credit on the date of the drawal the over drawn amount, irrespective of whether the over drawal occurred in the course of an advance or withdrawal or the final payment from the fund, shall be repaid by him within interest in one lumpsum, or in default, be ordered to be recovered by deduction in one lumpsum, from the emoluments

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

			of the subscriber. If the total amount to be recovered is more than half of the subscriber's emoluments.	
8. Regulation 13	13 Incentive Bonus Scheme	Deleted		
9. Regulation 14	14. Advance from the fund (1)	14(1)		
	(d) To meet the cost of legal proceedings instituted by the subscriber for vindicating his position in regard to any allegations made against him in respect of any act done or purported to be done by him in the discharge, of his official duty the advance being available in addition to any advance admissible for the same purpose from any other source.	“(d) to meet the cost of legal proceedings instituted by or against the subscriber, any member of his family or any person actually dependent on him, the advance in this case being available in addition to any advance admissible for the same purpose from any other source (Port)”. 2. xx xx 3. xx xx		
10. Regulation 15	15. Recovery of Advance—	(4) When an advance is sanctioned under sub-rule (2) before repayment of last instalment of any previous advance is completed the balance of any previous advance not recovered shall be added to the advance so sanctioned and the instalments for recovery shall be fixed with reference to the consolidated amount”. (5) No temporary advance shall be sanctioned during the last 3 months of service in order to enable the Accounts Officer to complete the task of issuing Authority for payment one month before the retirement.		
	(1)			
	(2)			
	(3) If an advance has been granted to a subscriber and drawn by him and the advance is subsequently disallowed before payment is completed, the whole or balance of the amount withdrawn, shall forthwith be repaid by the subscriber to the fund or in default be ordered by the Accounts Officer to be recovered by deduction from			

1 2

3

4

5

the emoluments of the subscriber in a lumpsum or in monthly instalments not exceeding 12 as may be as directed by the Chairman or the authority competent to sanction an advance under Explanation 2 to sub-regulation (3) of regulation 14.

“Provided that, before such advance is disallowed, the subscriber shall be given an opportunity to explain to the sanctioning authority in writing and within fifteen days of the receipt of the communication why the repayment should not be enforced and if an explanation is submitted by the subscriber within the said period of fifteen days, it shall be referred to the Chairman for decision, and if no explanation within the said period is submitted by him, the repayment shall be enforced in the manner prescribed in this sub-rule”.

#### FORM VI

(See regulation 14)

#### PROFORMA FOR APPLICATION OF ADVANCE FROM PROVIDENT FUND

Port of New Mangalore.

##### APPLICATION FOR ADVANCE FROM (here enter the name of Fund)

1. Name of subscriber.
2. Account number (with Departmental suffix)
3. Designation
4. Pay
5. Balance at credit of the subscriber on the date of application as below:
  - (i) Closing balance as per statement for the year.....
  - (ii) Credit from .....to.....  
subscription.....
  - (iii) Refunds
  - (iv) Withdrawals during the period from.....to.....
  - (v) Net balance at credit
6. Amount of advance outstanding if any and the purpose for which advance was taken then
7. Amount of advance required.

8. (a) Purpose for which advance is required  
(b) Rules under which the request is covered
9. Amount of the consolidated advances (Items 6 & 7) and number of monthly instalments in which the consolidate advance is proposed to be repaid.
10. Full particular of the pecuniary circumstances of the subscriber, justifying the application for the advance.

Signature of the applicant

Name \_\_\_\_\_

Designation .....

Section/Branch .....

### FORM VI

(Regulation 14)

Proforma for application for advance from Provident Funds

## New Mangalore Port Trust.

Department of ...../office

Application for Advance from.....

(Here enter the name of Fund)

1. Name of the subscriber
2. Account Number (with Departmental suffix)
3. Designation
4. Pay Rs.
- 5: Balance at credit of the subscriber on the date of application as below:
  - (i) Closing balance as per statement for the year.....Rs.
  - (ii) Credit from .... to..... on account of monthly subscription
  - (iii) Refunds Rs.
  - (iv) Withdrawals during the period from....to.... Rs.
  - (v) Net balance at credit Rs.

6. Amount of advance/outstanding, if any, and the purpose for which advance was taken by them

Amount of advance taken Rs.

Balance outstanding as on date Rs. ....



1	2	3	4	5
11. Regulation 16	16. Wrongful use or Advance:	Not with standing anything contained in these regulations if the Chairman is satisfied that money drawn as an advance from the fund under regulation 14 has been utilised for a purpose other than that for which sanction was given to the drawal of the money the amount in question shall forthwith be repaid by the subscriber to the fund, or in default ordered by the Chairman to be recovered by deduction, in one lump sum from the emoluments of the subscriber even if he be on leave. If the total amount to be repaid be more than half the subscriber's emoluments recovery shall be made in monthly instalments or moieties of his emoluments till the entire amount is repaid by him. Explanation : In this regulation, "emoluments" do not include subsistence grant.	"16. Wrongful use of Advance: Notwithstanding anything contained in this regulation, if the sanctioning authority has reason to doubt that money drawn as advance from the fund under Rule 14 has been utilised for a purpose other than that for which sanction was given to the drawal of the money. he shall communicate to the subscriber the reason for his doubt and require him to explain in writing and within fifteen days of the receipts of such communication whether the advance has been utilised for the purpose for which sanction was given to the drawal of money. If the sanctioning authority is not satisfied with the explanation furnished by the subscriber within the said period of fifteen days, the sanctioning authority shall direct the subscriber to repay the amount in question to the fund forthwith or, in default, order the amount to be recovered by deduction in one lumpsum from the emoluments of the subscriber even if he be on leave. If however the total amount to be repaid the more than half the subscribers emoluments, recoveries shall be made in monthly instalments of moieties of his emoluments till the entire amount is repaid by him".	
12. Regulation 17.	17. Withdrawal from the fund	(1)		Note : The term "emoluments in the rule does not include subsistence grant".
		(2) After the completion of 15 yeas of service of subscriber or within ten years before the date of his retirement of subscription and	"(2) After the completion of (ten years) of service (including broken periods of service if any) of a subscriber or within ten years before	

1	2	3	4	5
		interest thereon standing to the credit of the subscriber of the fund for one or more of the following purposes., Namely :	the date of his retirement on superannuation, which even is earlier, from the amount standing to his credit in the fund for one or more of the following purposes, namely :	
		(a)		
		(b)		
		(c) for constructing a house on a site purchased, utilising the sum withdrawn under clause (a)	“(c) Renovating, additions or alteration or up keep of an ancestral house at a place other than the place of duty or to a house built with the assistance of loan from the N.M.P.T. at a place other than the place of duty”.	
			“(d) for constructing a house on a site purchased, utilising a sum withdrawn under clause (a)”.	
			“(3) Within six months before the date of the subscriber's retirement, from the amount standing to his credit in the fund for the purpose of acquiring a farm land or business premises or both”.	
			“(4) Once during the course of a financial year, an amount equivalent to one year's subscription paid by the subscriber towards the group Insurance scheme for the employees organised by L.I.C. of India for NMPT on self financing and contributing basis”.	
		Note 1: Only one withdrawal shall be allowed for the same purpose under regulation 17. But marriage/education of different children or illness on different occasions shall not be treated as the same purpose.	Note 1: A subscriber who has availed himself of an advance under the NMPT for the grant of advance for house building purpose, or has been allowed any assistance in regard from any other recognised housing scheme shall be eligible for the grant of withdrawal under Sub- Clause (a), (c), (d) sub-regulation (2) of this regulation the purposes specified there in and also for the purpose of repayment of any loan taken under the aforesaid scheme subject to the limit specified in the provision to sub rule (1) of rule 18”.	
		2. A withdrawal under regulation 17 shall, not be sanctioned if an advance under regulation 14 is being sanctioned for the same purpose at the same time.		

1 2

3

4

5

If the subscriber has an ancestral house or built a house at a place other than the place of his duty with the assistance of loan taken from the Government he shall be eligible for the grant of a final withdrawal under this regulation for purchase of a house site or for construction of another house or for acquiring a ready built flat at the place of duty.

**Note 2:** Withdrawal under sub-clause (a), (c) and (d) of sub regulation 2 of this regulation shall be sanctioned only after a subscriber has submitted a plan of the house to be constructed or of the addition or alteration to be made and approved by the local municipal body of the area where the site of house is situated and only in cases where the plan is actually got approved.

**Note 3:** The amount of withdrawal sanctioned under for sub-clause (b) regulation 2 shall not exceed  $3/4$  of the balance on date of application together with the amount of previous withdrawal under sub-clause (a) reduced by the amount of previous withdrawal, the formula to be followed is  $3/4$ th of the balance as on date plus amount of previous withdrawal(s) for the house in question) minus the amount of previous withdrawal.

**Note 4:** Withdrawal under sub-clause (a) of sub regulation 2 shall also be allowed where the house site or home is in the name of wife or husband provided she or he is the first nominee to receive provident fund money in the nomination made by the subscriber.

1 2

3

4

5

Note 5: Only one withdrawal shall be allowed for the same purpose under this rule. But marriage or education of different children or illness on different occasions or a further addition or alteration to the house or flat covered by fresh plan duly approved by the local municipal body of the area where the house or flat is situated shall not be treated as the same purpose. Second, or subsequent withdrawal under sub-clause (a) or sub clause (c) of sub regulation (2) shall be allowed upto the limit laid down under note 3"

Note 6: A withdrawal under regulation 17 shall, not be sanctioned if an advance under regulation 14 is being sanctioned for the same purpose at the same time.

Note 7: No partial final withdrawal may be permitted during the last 3 months of service. However in exceptional cases this may be permitted under the sanction of the Head of the Department. Impressing on the employee concerned the possibility of delay in the issue of authority for final withdrawal one month before the retirement.

"(5) "In the following cases also part final/final withdrawals from the General Provident fund are allowed.

(a) Employees who have completed 15 years of service (including broken period of service if any) or who have less than 5 years to attain the age of superannuation may be permitted to make part final withdrawals from their Provident Fund for purchasing Motor Car/Motor Cycle or

1 2

3

4

5

Scooter etc. for repaying loan taken from the Port for this purpose subject to the following condition :

- (i) The employees' Basic pay should be the equivalent of Rs. 3,500/- P.M. in case of Motor Car and Rs. 1,500/- P.M. in the case of Motor Cycle/Scooter.
- (ii) The amount of withdrawals, limited to Rs. 25,000/- for purchase of Motor car and Rs. 4,000/- for the purchase of Motor Cycle/Scooter etc., Where the withdrawal has already been made for deposit for booking these vehicles, the employees will be eligible for drawal of only the balance amount and also subject to the over all ceiling limit prescribed here. The total amount of withdrawal for this purpose (deposit for booking plus the amount required for purchase) should not exceed 50 % of the amount standing to the credit of subscriber in the GPF account (including interest) on the date of withdrawal or the actual price of the vehicle whichever is less.
- (iii) In special cases an advance refundable in not more than 36 instalments in the case of employees who may fall short of the minimum service of 15 years by a period of not more than 6 months may be allowed by the Chairman.
- (iv) The employees who have been allowed advance according to (iii) above may be permitted to convert the outstanding balance of the advance into final withdrawal after completion of 15 years of service.

— 1

2

3

4

5

(v) Such withdrawal shall be allowed only on one occasion.

(b) Employees who have completed 28 years of service or who have less than 3 years to attain the age of superannuation may be permitted to make final withdrawals from Provident fund for extensive repair or overhauling of their Motor Cars subject to the following condition :

(i) Employees whose pay is equivalent to Rs. 1,400/-

(ii) Amount of withdrawal is limited to Rs. 5,000/- or 1/3rd of the amount standing to the credit of the subscriber in the G.P. Fund or the actual amount of repairing or overhauling whichever is the least.

(iii) Not less than 5 years should have elapsed since the car was purchased. In case of second hand cars the initial date of purchase by the first purchaser will be taken into account.

(iv) Such withdrawal shall be allowed only once in the service career of the subscriber.

(c) Employees who have completed 15 years of service (including broken period of service if any) may be permitted to make a part final withdrawal from the General Provident fund for booking a Motor Car/Motor Cycle/Scooter/Moped etc., subject to the following conditions :

(i) The employees basic should be equivalent to Rs. 3,500/- for Motor Car and Rs. 1500/- in case of Motor Cycle/Scooter etc.

1 2

3

4

5

(ii) The amount of withdrawal is limited to Rs. 10,000/- in the case of car and Rs. 500 in the case of Motor Cycle/Scooter etc. or 50 % of the amount standing to the credit of the subscriber in the G.P. Fund or the actual amount of registration in the case of Motor Cycle /Scooter etc. whichever is less;

(iii) The amount of withdrawal shall not exceed the amount required for booking a car or Motor Cycle or Scooter etc.

(iv) The deposit receipt must be produced for verification by the concerned administrative authority within a period of one month from the date of drawal. Failure to do so would involve refund of the total amount of withdrawal.

(v) If the employee does not purchase a car/Motor cycle, Scooter etc. or gets out of the scheme he should immediately deposit the amount of final withdrawal together with interest received thereon from the manufacturer/ dealer into the Provident Fund Account.

(vi) In special cases when the minimum service 15 years falls short by six months, advance recoverable in 26 instalments may be sanctioned and this is eligible for conversion into part final withdrawal after completion of 15 years of service.

(vii) Such withdrawal shall be allowed only on one occasion and subject to overall ceiling at present prescribed for withdrawal in G.P. Fund.

(6) "Whenever a subscriber is in a position to satisfy the competent authority about the amount standing to his

1 2

3

4

5

credit in the General Provident Fund Account with reference to the latest available statement together with the evidence of subsequent contribution, the competent authority may itself sanction withdrawal within the prescribed limits, as in the case of refundable advance. In doing so, the competent authority shall take into account any withdrawal or refundable advance already sanctioned by it in favour of the subscriber. Where, however, the subscriber is not in a position to satisfy the competent authority about the amount standing to his credit or where there is any doubt about the admissibility of the withdrawal applied for a reference may be made to the Accounts Officer by the competent authority for ascertaining the amount standing to the credit of the subscriber with a view to enable to the competent authority to determine the admissibility of the amount of withdrawal.

The sanction for the withdrawal should prominently indicate the General Provident Fund Account number and a copy of the sanction should invariably be endorsed to the Account Officer. In case the Accounts officer reports that withdrawal as sanctioned is in excess of the amount to the credit of the subscriber or otherwise inadmissible, the sums withdrawn by the subscriber shall forthwith be repaid in one lumpsum by the subscriber to the fund and in default of such repayment, it shall be ordered by the sanctioning authority to be recovered from his emoluments either

1 2

3

4

5

in lumpsum or in such number of monthly instalments,, as may be determined by the Chairman.

13. Regulation 18 18. Condition of Withdrawal :

(1) Any sum withdrawn by subscriber at any time for one or more purposes specified in regulation 17 from the amount standing to his credit in the fund shall not ordinarily exceed one half of such amount or six months' pay whichever is less. The sanctioning authority may however, sanction the withdrawal of an amount in excess of this limit upto three fourths of the balance at his credit in the fund, having due regard to:

(i) The object for which the withdrawal is made (ii) the status of the subscriber and (iii) the amount to his credit in the fund.

“Provided that in no case the maximum amount of withdrawal for purposes specified in sub-regulation 2 under Regulation 17 shall exceed the maximum limit prescribed from time to time under Regulation 4, 5 and 6 of the New Mangalore Port Trust Employees (Grant of advance for Building House).

Regulation 1980, for the grant of advance for house building purpose.

‘Provided that in the case of subscriber who has availed himself of an advance under the NMPT Employee (Grant of Advances for Building of Houses) Regulations 1980 or has been allowed assistance from any other approved scheme the sum withdrawn under this sub-regulation together with the amount of advance taken under the above sources shall not exceed the maximum limit prescribed from time to time under the

1 2

3

4

5

NMPT Employees (Grant of Advance for Building of Houses) Regulations 1980.

Note :—A withdrawal sanctioned to a subscriber under sub-clause(a) of sub-regulation 2 of regulation 17 may be drawn in instalments the number of which shall not exceed from in a period of twelve calendar months counted from the date of sanction.

“Note :—In case when a subscriber has to pay in instalments for a site or a house or flat purchased, or a house or flat constructed through the various schemes approved by the Government of India or a House Building Co-operative Society, he shall be permitted to make a withdrawal as and when he is called upon to make payment in any instalment. Every such payment shall be treated as a payment for a separate purpose for the purposes of sub rule(1) of rule 16.

(2) A subscriber who has been permitted the withdrawal of money under regulation 17 shall satisfy the sanctioning authority within a reasonable period as may be specified by that authority that the money has been utilised for the purpose for which it was withdrawn and if fails to do so, the whole of the sum so withdrawn or so much thereof as has not been applied for such purposes for which it was withdrawn, shall forthwith, be repaid into one lumpsum together with interest thereon at the rate determined under regulation 12 by the subscriber to the fund and in default of such payment, it shall be ordered by the sanctioning authority to be recovered from his emoluments, either in a lumpsum or any

1

2

3

4

5

such number of monthly instalments as may be determined by the Chairman.

“Provided that, before repayment of a withdrawal is enforced under this sub regulation, the subscriber shall be given an opportunity to explain in writing and within fifteen days of the receipt of the communication why the repayment shall not be enforced and if the sanctioning authority is not satisfied with the explanation or no explanation is submitted by the subscriber within the said period of fifteen days, the sanctioning authority shall enforce the repayment in the manner prescribed in this sub regulation”.

(3) A subscriber, who has been permitted under regulation (2) of regulation 17 to withdraw money from the amount standing to his credit in the fund, shall not part with the possession of the house so built or, acquired for house site so purchased, by way of sale, Mortgage (other than mortgage to the sanctioning authority) or gift, without the previous permission of the sanctioning authority. He shall also not part with the possession of such house or house site by way of exchange or lease for a term exceeding three years without the previous permission of the sanctioning authority. The subscriber shall submit a declaration not later than 31st day of December of every year to the effect as to whether the house or house site as the case may be, continues to be his possession or has been mortgaged or otherwise transferred and shall, if so required, produce before the sanctioning authority on or

(3) A subscriber, who has been permitted under regulation (2) or regulation 17 to withdraw money from the amount standing to his credit in the fund, shall not part with the possession of the house so built or, acquired for house site so purchased, by way of sale, mortgage (other than mortgage to the sanctioning authority) or gift, without previous permission of the sanctioning authority. He shall also not part with the possession of such house or house site by way of exchange or lease for a term exceeding three years without the previous permission of the sanctioning authority. The subscriber shall submit a declaration not later than the 31st day of December of every year to the effect as to whether the house or house site, as the case may be continuous to be in his possession or has been mortgaged or otherwise transferred or let out as aforesaid and shall, if so required, produce before the sanctioning

1

2

3

4

5

before the date of specified by that authority in that behalf, the original sale deed and other documents on which his title to the property is based.

authority or or before the date specified by that authority in that behalf, the original mortgage or lease deed and also the the other documents on which his title to the property is based.

“Provided such permission shall not be necessary for its being mortgaged in favour of a Housing Board, Nationalised Bank, the Life Insurance Corporation or any other Corporation owned or controlled by the Central Government which advance loans for the construction of a new House or for making addition or alteration to an existing house.

(4) If at any time before retirement the subscriber parts with the possession of the house or house site without obtaining the previous permission of the sanctioning authority the sum withdrawn by him shall forthwith be repaid in one lumpsum to the fund and in default of such repayment it shall be ordered by the sanctioning authority to be recovered from his emoluments either in a lumpsum or in lumpsum or in such number or monthly instalments as may be determined by the Board.

(4) If at any time before retirement the subscriber parts with the possession of the house or house site without obtaining the previous permission of the sanctioning authority the sum withdrawn by him shall forthwith be repaid in one lumpsum to the fund and in default of such repayment after giving the subscriber a reasonable opportunity of making a representation in the matter it shall be ordered by the sanctioning authority to be recovered from his emoluments either in a lumpsum or in such number of monthly instalments as may be determined by the Board.

“Note :—A subscriber who has taken a loan from the NMPT and in lieu thereof mortgaged the house or house site to the Port Trust Board shall be required to furnish the declaration to the following effect, namely :—

“I do hereby certify that the house or house site for the construction of which or for the acquisition of which I have taken a final withdrawal from

1 2

3

4

5

the Provident Fund continues to be in my possession by stands mortgaged to the Port Trust Board".

(5) A subscriber should not be granted a second withdrawal for house building purposes at any place if he has already been granted a final withdrawal for similar purposes at the same or another place. In other words, final withdrawals should not be allowed for more than one house."

## 14. Regulation 19

19. Conversion of an advance into a withdrawal : A subscriber who has already drawn or may draw in future an advance under regulation 14 for any of the purpose, specified in sub-clauses (b) and (c) of sub-regulation (1) or regulation 17, may convert, at his discretion, by a written request addressed to the Accounts officer through the sanctioning authority, the balance outstanding against him into a final withdrawal on his satisfying the conditions laid down in regulations 17 and 18.

19. Conversion of an advance into a withdrawal :—A subscriber who has already drawn or may draw in future an advance under regulation 14 for any of the purpose, specified in sub-regulation (1) to (4) of Regulation 17, may convert, at his discretion by a written request addressed to the Accounts Officer through sanctioning authority, the balance outstanding against him into a final withdrawal/ on his satisfying the conditions laid down in regulations 17 and 18.

"Note :—For the purpose of sub-regulation 1 of rule 17 the amount of subscription with interest thereon standing to the credit of the subscriber in the account at the time of conversion plus the outstanding amount of advance shall be taken as the balance. Each withdrawal shall be treated as a separate one and the same principle shall apply in the event of more than one conversion."

1 2

3

4

5

Form IX A  
(Regulation 19)

Form of Application for conversion of an advance into a final withdrawal.

1. Name of the subscriber—
2. Designation and office to which attached—
3. Pay—
4. Name of the Provident Fund and Account Number—
5. Balance at credit on the date of application(amount actually subscribed by him alongwith interest due thereon in the case of G.P.F. subscriber)—
6. (a) Balance outstanding to be converted into a final withdrawal—  
(b) Interest due on the amount of advance taken.—
7. (a) Purpose for which advance taken—  
(b) Date of payment of the advance—  
(c) Amount of advance sanctioned—
8. Particulars of communication under which advance was sanctioned—
9. Whether any advance or final withdrawal has been drawn previously for the purpose mentioned above. If so, particulars thereof.
10. (a) Total service, including broken periods, if any, on date of this application—  
(b) Period of service left on the date of application for attaining the age of superannuation—

(c) The date of superannuation :—

Place :

Date :

Signature of the

**Applicant**

Dated :

The above particulars have been verified to be correct.

Signature and  
designation of  
recommending authority

## ORDER

No. Dated.....

Sanction of ..... is hereby conveyed/accorded under Rule 19 of NMPT (GPF) Regulation, 1980, for the conversion into final withdrawal of an amount of Rs. .... Rupees ..... only) being the outstanding balance out of the GPF advance of Rs. .... sanctioned on ..... 19.... and drawn in Bill No ..... of ..... for the (purpose) ..... to Sri/Smt./ Kumari ..... of the office of the ..... (G.P.F. Account No. .... )

Signature.....

Designation.....

No.

Copy forwarded to:

(i)

(ii)

(iii). . . . . etc. etc.

Signature : .....

Designation .....

1 2

3

4

5

15. Regulation 27. 27. Relaxation of the provisions and regulations in individual cases—When the Board is satisfied that the operation of any of these regulations causes, or is likely to cause, undue hardship to a subscriber, the Board may, notwithstanding anything contained in these regulations, deal with the case of such subscriber in such manner as may appear to it to be just and equitable. deleted

16. Regulation 28. 28. Number of account to be quoted at the time of payment of subscription when paying subscription in India, either by deduction from emoluments or in cash, a subscriber shall quote the number of his account in the fund which shall be communicated to him by the Accounts Officer. Any change in the number shall similarly be communicated to the subscriber by the Accounts Officer.

27. Number of account to be quoted at the time of payment of subscription when paying subscription in India, either by deduction from emoluments or in cash, a subscriber shall quote the number of his account in the fund which shall be communicated to him by the Accounts Officer. Any change in the number shall similarly be communicated to the subscriber by the Accounts Officer.

17. Regulation 29. Annual statement of accounts to be supplied to subscribers—(1) As soon as possible after the close of each year, the Accounts Officer shall send to each subscriber a statement of his accounts in the fund showing the opening balance as on the 1st April of the year the total amount credited as on the 31st March of the year and the closing balance on that date. The Accounts Officer shall attach to the statement of account on enquiry whether the subscriber—

(a) desires to make any alteration in any nomination made under regulation 6 or under the corresponding regulation in force earlier;

(b) has acquired a family in cases where the subscriber has made no nomination in favour of a member of his family under regulation 6.

28. Annual statement of accounts to be supplied to subscribers—(1) As soon as possible after the close of each year, the Accounts Officer shall send to each subscriber a statement of his accounts in the fund showing the opening balance as on the 1st April of the year, the total amount credited as on the 31st March of the year and the closing balance on that date. The Accounts Officer shall attach to the statement of account on enquiry whether the subscriber—

(a) desires to make any alteration in any nomination made under regulation 6 or under the corresponding regulation in force earlier;

(b) has acquired a family in cases where the subscriber has made no nomination in favour of a member of his family under regulation 6.

(2) Subscribers shall satisfy themselves as to the correctness of the annual statement, and they shall bring to the notice of the Accounts Officer within three months from the date of receipt of the statement by them any inaccuracy or error in such statement.

(3) The Accounts Officer, shall, if required by a subscriber, once but not more than once, in a year inform the subscriber of the total amount standing in his credit in the fund at the end of the last month for which his account has been written up.

## 18. Regulation 30.

## 30. Deposit linked insurance scheme :-

On the date of subscriber, the person entitled to receive the amount standing to the credit of the subscriber shall be paid by the Accounts Officer an additional amount equal to the average balance in the account during the 3 years immediately preceding the death of such subscriber subject to the condition that:-

(a) The balance at the credit of such subscriber shall be not any time during the 3 years preceding the month of death have below the limits of,

- (i) Rs. 4000 in the case of subscriber who held, for the greater part of the aforesaid period of three years, a post the maximum of the pay scale of which is Rs. 1300 or more;
- (ii) Rs. 2300 in the case of a subscriber who has held, for the greater part of the aforesaid period of three years, a post the maximum of the pay scale of which is Rs. 900 or more but less than Rs. 1300;
- (iii) Rs. 1,500 in the case of subscriber who has held, for the greater part of the aforesaid period of three years, a post maximum of the pay scale of which is Rs. 290 or more but less than Rs. 900;

(2) Subscribers shall satisfy themselves as to the correctness of the annual statement, and they shall bring to the notice of the Accounts Officer within three months from the date of receipt of the statement by them any inaccuracy or error in such statement.

(3) The Accounts Officer, shall, if required by a subscriber, once but not more than once, in a year inform the subscriber of the total amount standing in his credit in the fund at the end of the last month for which his account has been written up.

## 29. Deposit linked Insurance scheme :-

On the date of a subscriber, the person entitled to receive the amount standing to the credit of the subscriber shall be paid by the Accounts Officer an additional amount equal to the average balance in the account during the 3 years immediately preceding the death of such subscriber subject to the condition that :-

(a) The balance at the credit of such subscriber shall not at any time during the 3 years preceding the month of death have below the limits of,

- (i) Rs. 4,000 in the case of a subscriber who held, for the greater part of the aforesaid period of three years, a post the maximum of the pay scale of which is Rs. 1,300 or more;
- (ii) Rs. 2,500 in the case of subscriber who has held for the greater part of the aforesaid period of three years, a post the maximum of the pay scale of which is Rs. 900 or more but less than Rs. 1,300;
- (iii) Rs. 1,500 in the case of subscriber who has held, for the greater part of the aforesaid period of three years, a post the maximum of the pay scale of which is Rs. 290 or more but less than Rs. 900;

1	2	3	4	5
		(iv) Rs.1,000 in the case of a subscriber who has held, for the greater part of the aforesaid period of three years, a post the maximum of the pay scale of which is less than Rs. 290.	(iv) Rs.1,000 in the case of a subscriber who has held, for the greater part of the aforesaid period of three years, a post the maximum of the pay scale of which is less than Rs.290.	
		(b) the additional amount payable under this regulation shall not exceed Rs.10,000.	(b) the additional amount payable under this regulation shall not exceed Rs.10,000.	
		(c) the subscriber has put in at least 5 years service at the time of his death, including the service in the Port of New Mangalore, before the formation of the Port Trust.	(c) the subscriber has put in at least 5 years service at the time of his death, including the service in the part of New Margalore, before the formation of the Port Trust.	
		NOTE 1 : The average balance shall be worked out on the basis of the balance at the credit of the subscriber at the end of each of the 36 months preceding the month in which the death occurs. For this purpose, as also for checking the minimum balances prescribed above—	NOTE 1 : The average balance shall be worked out on the basis of the balance at the credit of the subscriber at the end of each of the 36 months preceding the month in which the death occurs. For this purpose, as also for checking the minimum balances prescribed above—	
		(a) The balance at the end of March shall include the annual interest credited in terms of regulation 12; and	(a) The balance at the end of March shall include the annual interest credited in terms of regulation 12; and	
		(b) If the last of the aforesaid 36 months is not March, the balance at the end of the said last month shall include interest in respect of the period from the beginning of the financial year in which death occurs to the end of the said last month.	(b) If the last of the aforesaid 36 months is not March, the balance at the end of the said last month shall include interest in respect of the period from the beginning of the financial year in which death occurs to the end of the said last month.	
		NOTE 2 : Payment under this scheme shall be in whole rupees. If an amount due includes a fraction of a rupee, it should be rounded to the nearest rupee, (50 paise counting as the next higher rupee).	NOTE 2 : Payment under this scheme shall be in whole rupees. If an amount due includes a fraction of a rupee, it should be rounded to the nearest rupee, (50 paise counting as the next higher rupee).	
		NOTE 3 : Any sum payable under this scheme is in the nature of insurance money and, therefore, the statutory protection given by section 3 of the Provident Funds Act, 1925 (19 of 1925), does not apply to sums payable under this scheme.	NOTE 3 : Any sum payable under this scheme is in the nature of insurance money and, therefore, the statutory protection given by section 3 of the Provident Funds Act, 1925 (19 of 1925), does not apply to sums payable under this scheme.	

1 2

3

4

5

NOTE 4 : In case of persons appointed on tenure basis and in the case of re-employed pensioners, service rendered from the date of such appointment to re-employment, as the case may be, only shall count for purpose of this rule.

NOTE 4 : In case of persons appointed on tenure basis and in the case of re-employed pensioners, service rendered from the date of such appointment to re-employment, as the case may be, only shall count for purpose of this rule.

“NOTE 5 :—The Budget estimates of expenditure in respect of this scheme will be prepared by the Accounts Officer having regard to the trend of expenditure, in the same manner as estimates are one prepared for other retirement benefits”.

(c) This scheme does not apply to person appointed on contract basis.

(c) This scheme does not apply to person appointed on contract basis.

19. Regulation 31. Interpretation—If any question arises relating to the interpretation of these regulations, it shall be decided by the Central Government.

30. Interpretation—If any question arises relating to the interpretation of these regulations, it shall be decided by the Central Government.

